मीडिया मैप

उदार जनतंत्र का सजग प्रहरी

● वर्ष : 10 ● अंक : 06 ● जून : 2025 ● पृष्ठ : 40 ● मूल्य : 50/-

■ युद्ध खत्म : चुनाव प्रचार शुरू ■ ग्यारह साल बाद : मोदी का भारत आकांक्षाओं और आंदोलनों के बीच ■ मोदी सरकार की 'बैलेंसिंग एक्ट' की बात महज दिखावा

: हम क्यों :

मीडिया मैप एक वैचारिक पत्रिका है। हमारे समाज के नीतिपरक और मूल्यनिष्ठ बिन्दु तथा इनसे जुड़ाव रखने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक मुद्दे इसकी विषयवस्तु है। मीडिया मैप की संपादकीय नीति उदारवादी, आधुनिक, प्रगतिशील व सर्व धर्म समभाव की भावना पर आधारित है।

मीडिया मैप हमारे बहुलतावादी समाज की विविधताओं से सृजित समस्त सोच, विचार, दृष्टिकोण, मूल्य और मान्यताओं को अपने में समाहित करने का एक प्रयास है। हमारा उद्देश्य वैज्ञानिक सोच द्वारा समाज से जुड़े मूल मुद्दों पर एक प्रबुद्ध जनमत विकसित करना है, जिससे देश में संकुचित मानसिकता और आपसी टकराव से ऊपर उठकर एक उच्चस्तरीय विचार-विमर्श का वातावरण तैयार हो सके।

मीडिया मैप

उदार जनतंत्र का सजग प्रहरी

संपादकीय सलाहकार मंडल
डॉ. बलदेवराज गुप्त
के.बी. माथुर
डॉ. सलीम खान

प्रधान संपादक
प्रो. प्रदीप माथुर

संयुक्त संपादक : डॉ. सतीश मिश्रा
सहायक संपादक : प्रो. शिवाजी सरकार
विज्ञान तकनीकी संपादक : राजीव माथुर
विशेष प्रतिनिधि : डॉ. मुज़फ्फर गज़ाली
मुख्य उप संपादक : जितेन्द्र मिश्र
वरिष्ठ उप संपादक : प्रशांत गौतम
उप संपादक : अंकुर कुमार

प्रबंध संपादक : चन्द्र कुमार एडवोकेट
प्रबंधक : जगदीश गौतम
विधि परामर्शदाता : संजय माथुर

पंजीकृत कार्यालय : 2324, सेक्टर-डी
पॉकेट-2, वसंत कुंज, नई दिल्ली

संपादकीय कार्यालय : 70 ज्ञानखंड-4, इंदिरापुरम
गाजियाबाद- 201014 (उत्तर प्रदेश)

दूरभाष : 9810385757/9910069262
एम बी के एम फाउंडेशन प्रकाशन

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक प्रदीप माथुर द्वारा लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली से मुद्रित एवं मकान नंबर 70, ज्ञानखंड-4, इंदिरापुरम, जनपद-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201014 से प्रकाशित।

सभी लेखों में लेखकों के अपने उल्लेखित विचार हैं। लेखों और विचारों को लेकर किसी तरह का विवाद होने पर पत्रिका के संपादक, प्रकाशक, मुद्रक इसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जिला और न्यायालय गाजियाबाद ही होगा। इस पत्रिका से जुड़े सभी पदाधिकारी, सहयोगी और लेखक अवैतनिक हैं। पीआरबी एक्ट के तहत संपादक प्रो. प्रदीप माथुर उत्तरदायी हैं।

RNI No. : UPHIN/2016/68336

अनुक्रमणिका

4 संपादकीय : स्वस्थ सामाजिक पर्यावरण की महती आवश्यकता

विचार-प्रवाह : ईरानी मिसाइलों ने अडानी को जोर का झटका दिया 5-6

7 सोशल मीडिया से : राष्ट्रीय एकता

युद्ध खत्म : चुनाव प्रचार शुरू : डॉ. मुज़फ्फर हुसैन ग़ज़ाली 8-9

10-11 अंग्रेजों पर अमित शाह की अनावश्यक टिप्पणी : डॉ. सतीश मिश्रा

वक्फ बिल से बीजेपी का जनाधार होगा प्रभावित : प्रो. प्रदीप माथुर 12

13-14 भारत ने जापान को वैश्विक GDP रैंकिंग में पीछे छोड़ा

मोदी सरकार की 'बैलेंसिंग एक्ट' की बात महज दिखावा 15-16

17-18 हमारी स्वास्थ्य मुहिम सिर्फ तेल नहीं आजीविका भी जला सकती है

नूर खान एयरबेस पर भारत की ऐतिहासिक स्ट्राइक से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे 19

20-21 ग्यारह साल बाद : मोदी का भारत आकांक्षाओं और आंदोलनों के बीच

एयर इंडिया फ्लाइट 182 की याद में... प्रभजोत सिंह 22

23 भारतीय सिनेमा में वेब सीरीज का बढ़ता प्रभाव

नेहरू जी की इतनी कटु आलोचना क्यों 24-25

27 जीवन के सभी मुद्दों का स्थाई समाधान है 'भगवत गीता'

पहले टेस्ट के लिए मंच तैयार : सभी की निगाहें टीम संयोजन पर 31-33

34-35 मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मंत्री विजय शाह पर एफआईआर का अभूतपूर्व आदेश

हम सब एक हैं-डार्विन की वैज्ञानिक चेतना आज और ज़रूरी है 36

37 हास्य व्यंग : एक उभरते नेता का इतिहास बोध

Email : editor@mediamap.co.in

प्रो. प्रदीप माथुर

♦♦

समाज में हर स्तर पर अराजकता और असुरक्षा का माहौल बनता जा रहा है। आर्थिक प्रगति और तकनीकी विकास के बावजूद, सामाजिक रिश्तों की नींव हिल रही है। संयुक्त परिवार ही नहीं, एकल परिवार भी टूट रहे हैं। अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। महिलाओं पर हिंसा, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा और बलात्कार की घटनाएं समाज को झकझोर रही हैं–और अबोध बच्चियां तक इस हिंसा की शिकार हो रही हैं। छोटी-छोटी बातों पर सड़क पर झगड़े और हत्या तक की घटनाएं आम हो चुकी हैं। पड़ोस में, जहाँ कभी सहयोग और स्नेह का वातावरण होता था, अब अक्सर कलह और टकराव देखने को मिलते हैं। यह सबसे बड़ा विरोधाभास है कि एक ओर धार्मिक आस्था चरम पर है–मंदिरों में भीड़, तीर्थस्थलों पर लंबी कतारें, कीर्तन-भजन की ध्वनि और नए-नए मंदिरों का निर्माण–जबकि दूसरी ओर नैतिक पतन और सामाजिक अपराध बढ़ते जा रहे हैं। यह सवाल उठता है कि क्या धर्म का यह उदय समाज को बेहतर बना पा रहा है? या क्या हमने धर्म को केवल एक बाह्य प्रदर्शन बना दिया है, जिसका जीवन की आंतरिक नैतिकता से कोई संबंध नहीं रहा?

♦♦

संपादकीय

स्वस्थ सामाजिक पर्यावरण की महती आवश्यकता

जून का महीना अक्सर पर्यावरण की चिंता और चेतना का समय होता है। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने है और हालिया रिपोर्टों के अनुसार, तापमान वृद्धि का सबसे अधिक प्रभाव एशिया पर पड़ रहा है। यह सच है कि हमें प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, लेकिन भारत में एक और भी गंभीर संकट उभर रहा है—हमारे सामाजिक पर्यावरण का।

आज भारतीय समाज एक गहरे सामाजिक विघटन से गुजर रहा है। पुराने मूल्य, रीति-रिवाज और नैतिक आधार समाप्त होते जा रहे हैं, जबकि नए मूल्य अभी स्थिर रूप से स्थापित नहीं हो पाए हैं। समाज में हर स्तर पर अराजकता और असुरक्षा का माहौल बनता जा रहा है। आर्थिक प्रगति और तकनीकी विकास के बावजूद, सामाजिक रिश्तों की नींव हिल रही है। संयुक्त परिवार ही नहीं, एकल परिवार भी टूट रहे हैं।

अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। महिलाओं पर हिंसा, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा और बलात्कार की घटनाएं समाज को झकझोर रही हैं—और अबोध बच्चियां तक इस हिंसा की शिकार हो रही हैं। छोटी-छोटी बातों पर सड़क पर झगड़े और हत्या तक की घटनाएं आम हो चुकी हैं। पड़ोस में, जहाँ कभी सहयोग और स्नेह का वातावरण होता था, अब अक्सर कलह और टकराव देखने को मिलते हैं।

यह सबसे बड़ा विरोधाभास है कि एक ओर धार्मिक आस्था चरम पर है—मंदिरों में भीड़, तीर्थस्थलों पर लंबी कतारें, कीर्तन-भजन की ध्वनि और नए-नए मंदिरों का निर्माण—जबकि दूसरी ओर नैतिक पतन और सामाजिक अपराध बढ़ते जा रहे हैं। यह सवाल उठता है कि क्या धर्म का यह उदय समाज को बेहतर बना पा रहा है? या क्या हमने धर्म को केवल एक बाह्य प्रदर्शन बना दिया है, जिसका जीवन की आंतरिक नैतिकता से कोई संबंध नहीं रहा?

इस सामाजिक पतन को केवल कानून से नहीं रोका जा सकता। आवश्यकता है एक गहरे सामाजिक पुनर्जागरण की। महात्मा गांधी ने अपने व्यवहार, सादगी और आत्मीयता से समाज के निचले वर्गों को जोड़ा था। आज नेताओं, नीति-निर्माताओं और प्रभावशाली वर्ग को भी ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। जब तक समाज के सभी वर्गों में नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना नहीं होगी, तब तक कोई स्थायी सुधार संभव नहीं।

समाज को दिशा देने के लिए अब केवल उपदेश नहीं, बल्कि प्रेरक आचरण की जरूरत है—ताकि हर व्यक्ति खुद को इस सामाजिक सुधार का हिस्सा समझे। यही एकमात्र रास्ता है, जिससे हम इस सामाजिक विकृति को रोक सकते हैं और एक सशक्त, सुरक्षित और नैतिक भारत की ओर बढ़ सकते हैं।

विचार-प्रवाह

ईरानी मिसाइलों ने अडानी को जोर का झटका दिया

रणनीतिक बंदरगाह हाइफ़ा में साहसिक प्रवेश, जो भू-राजनीतिक दृष्टि से अत्यधिक प्रतीकात्मक महत्व रखता है, ईरानी मिसाइलों की चपेट में आ गया है। भारत इस क्षेत्र में 600 अरब डॉलर के निवेश की योजना बना रहा है, यह जानकारी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) पर आयोजित एक बैठक में दी। ईरान को भारत का मित्र माना जाता है। लेकिन उनकी मिसाइलों ने इज़राइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी 'बाज़ान' को निशाना बनाया, जिससे हाइफ़ा पोर्ट कॉम्प्लेक्स में सभी परिचालन बंद हो गए। ईरानी मिसाइल हमले से भारी नुकसान हुआ है। हमले में तीन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई और महत्वपूर्ण ऊर्जा अवसंरचना में भीषण आग लग गई। Haaretz (एक वामपंथी झुकाव रखने वाला इज़रायली अखबार) द्वारा रिपोर्ट की गई तस्वीरों में रिफाइनरी आग की लपटों में घिरी हुई दिख रही थी और आपातकालीन कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। हाइफ़ा को बंद करना ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की उस श्रृंखला का हिस्सा था, जिसने तेल अवीव और हाइफ़ा को निशाना बनाया। इन हमलों में कम से कम आठ लोगों की मौत हुई और बड़े पैमाने पर तबाही हुई। रिहायशी इलाके मलबे में तब्दील हो गए और महत्वपूर्ण अवसंरचना को नुकसान पहुंचा—यह हाल के वर्षों में ईरान और इज़राइल के बीच सबसे प्रत्यक्ष टकरावों में से एक है।

विश्लेषकों का मानना है कि यह हमला केवल इज़राइल से विवाद तक सीमित नहीं था। इसने भारतीय उपक्रमों और IMEC की संभावनाओं पर भी असर डाला है। प्रथम विश्व युद्ध तक यह क्षेत्र ओटोमन खलीफ़ा के अनुयायियों के दान से बनी हेज़ाज़ नैरो-गेज रेलवे से तुर्की से जुड़ा हुआ था, जो दमिश्क और मदीना से हाइफ़ा तक जाती थी। शायद किसी रणनीतिकार ने यह नहीं सोचा होगा कि ईरान इज़राइल के सुदूर कोने हाइफ़ा को निशाना बनाएगा, जो भूमध्यसागर के किनारे स्थित है और यूरोप का प्रवेश द्वार माना जाता है। हाइफ़ा अपने विविध जनसंख्या, ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक जीवंतता के लिए जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, 23 सितम्बर 1918 को, भारतीय सैनिकों (मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर की रियासतों से) ने ब्रिटिश सेना की सहायता से हाइफ़ा को ओटोमन्स से मुक्त कराया था। यह स्वतंत्र इज़राइल (1948) की स्थापना की दिशा में पहला बड़ा कदम था। क्या अब भारत अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करेगा? अभी तक इसकी कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस हमले से भारत के हितों को नुकसान हुआ है, विशेषकर अडानी समूह के प्रारंभिक 1.2 अरब डॉलर के निवेश को। रिलायंस, एलएंडटी और कुछ अन्य भारतीय कंपनियों ने भी हाइफ़ा और IMEC में निवेश किया हुआ है।

अडानी समूह IMEC पहल में गहराई से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से बंदरगाह विकास और लॉजिस्टिक्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए। अडानी द्वारा हाइफ़ा पोर्ट में 70% हिस्सेदारी का अधिग्रहण और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अन्य रणनीतिक बंदरगाहों की खरीद भारत के IMEC लक्ष्यों के अनुरूप है। यह कॉरिडोर भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार, संपर्क और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, और अडानी का निवेश इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि हाइफ़ा, अडानी समूह के लिए एक छोटा बंदरगाह हो सकता है—भारत में इसके 13 बंदरगाह हैं जो देश के समुद्री कार्गो का एक-चौथाई संभालते हैं—फिर भी हाइफ़ा का महत्व उसके आकार से नहीं, बल्कि उसके प्रतीकात्मक महत्व से है।

यह भारत की उस साहसिक पहल का प्रतीक है, जिसमें उसने अस्थिर भू-राजनीतिक क्षेत्र में रणनीतिक अवसंरचना को संचालित करने का निर्णय लिया। जैसे-जैसे संघर्ष गहराते जा रहे हैं और क्षेत्रीय संतुलन बदल रहा है, हाइफ़ा भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षा और जोखिम सहने की क्षमता की परीक्षा बनता जा रहा है। इस बढ़ते टकराव के बीच भारत के रणनीतिक हितों पर ध्यान केंद्रित हो गया है—विशेष रूप से अडानी समूह द्वारा 2023 में अधिग्रहित हाइफ़ा पोर्ट पर। भले ही यह बंदरगाह अभी भी चालू है, लेकिन अब यह एक खतरनाक अग्रिम मोर्चे के किनारे पर स्थित है। 14 जून की रिपोर्टों में पुष्टि हुई कि ईरानी मिसाइल के टुकड़े पोर्ट के पास गिरे, जिससे एक केमिकल टर्मिनल और रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ। इन हमलों की निकटता पश्चिम एशिया में भारतीय परिसंपत्तियों के लिए बढ़ते खतरों को दर्शाती है। जो कभी एक साहसिक व्यापारिक कदम माना जाता था, वह अब एक सैन्यीकृत होते क्षेत्र में भारत की दृढ़ता की परीक्षा बन गया है। यह कई और छिपे हुए सवाल उठाता है, जिसमें चीन के साथ भारत की सीमा-पार प्रतिस्पर्धा और मुकाबला शामिल है। यह वैश्विक निवेश पैटर्न को भी बदल सकता है।

■ **शिवाजी सरकार**

विचार-प्रवाह

भारत में अंधराष्ट्रवाद (जिंगोइज़्म)

भारत भर में अंधराष्ट्रवाद (जिंगोइज़्म) केवल बढ़ नहीं रहा है, बल्कि पूरे जोश में है। 'बस एक बार न्यूक मार दो और सब खत्म कर दो। आतंकवाद का यही एकमात्र हल है,' एक अंधराष्ट्रवादी आम नागरिक कहता है। वह भूल गया कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को दो दशकों तक पत्थर युग में धकेल दिया— और अंत में चाबी तालिबान को ही वापस सौंप दी। इराक और लीबिया को मिटा दिया, मो. गद्दाफी और सद्दाम हुसैन की हत्या कर दी। अब वही सीरियाई आतंकवादी, जिन्हें अमेरिका ने 'आतंकवादी' घोषित किया था, उन्हें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ही सम्मानित कर रहे हैं। हां, ट्रंप सीरिया, गाज़ा और कई अन्य देशों में ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं, या उनकी कंपनियां यूक्रेन के खनिजों पर अधिकार पाने की कोशिश में हैं। और सबने रूस और यूक्रेन के उन बहादुर सिपाहियों को भूल दिया है जिन्होंने अपनी जानें दीं— शायद उन्हें खुद नहीं पता था किस लिए। राष्ट्रवाद अब एक घिसा-पिटा नारा बन गया है, जिसके नाम पर लोग किसी भी देश में अपनी जान देने को तैयार हैं, और वैश्विक नेता एक-दूसरे से जाम टकराकर 'शांति' के नाम पर एक और युद्ध की साजिश रचते हैं। कश्मीर में, जहां लोग हमेशा हिंसा के साए में जीते हैं, 22 अप्रैल के आतंकी हमले और 6 मई की भारतीय जवाबी कार्रवाई के बीच थोड़ी देर के लिए यह चर्चा हुई कि 'चलो एक बार में फैसला कर लें।' लेकिन जैसे ही घाटी में पहले धमाके हुए, वह घमंड हवा हो गया। बम धमाके टीवी बहसों या व्हाट्सऐप फॉरवर्ड्स जैसे नहीं होते—वे आपकी हड्डियां हिला देते हैं। यही फर्क है जंग से जूझने और एसी कमरे में बैठकर बहस करने में। नोएडा की टीवी ब्रिगेड, जिसे अब लश्कर-ए-नोएडा भी कहा जा रहा है, जितना चाहे चिल्ला ले, लेकिन कोई सीमा पर जाकर जान देने को तैयार नहीं। उनकी चीखों से सिर्फ विज्ञापन और प्रायोजित समर्थन बढ़ता है। कम से कम 19 लोग पाकिस्तानी गोलाबारी में पूंछ में मारे गए और कई हजार बेघर हो गए, लेकिन किसी ने उनके लिए आंसू नहीं बहाए। युद्ध से सिर्फ हथियारों के सौदागरों की ही नहीं, बल्कि इस कोलाहल को पैदा करने वालों की भी जेबें भरती हैं— ताकि और अधिक हथियार खरीदे जाएं।

भारत और पाकिस्तान दोनों ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भयावह कमी से जूझ रहे हैं। सिर्फ उत्तेजित टीवी एंकर ही नहीं, आम नागरिक—इंजीनियर, शिक्षक, अंकल लोग—युद्ध को ऐसे चीयर करते हैं जैसे यह आईपीएल का फाइनल हो या कोई नेटफ्लिक्स थ्रिलर। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम के बाद 'जीत' का दावा किया। कूटनीतिक रूप से शायद कुछ सफलता मिली हो, लेकिन सैन्य रूप से कतई नहीं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और संघर्ष विराम की मांग की। अमेरिका कहता है कि बैक चैनल थे, लेकिन इतिहास सिर्फ आधिकारिक रिकॉर्ड को याद रखेगा-पाकिस्तान ने पहले झुका। इस बीच भारत पेड़ों की आग में जंगल भूल गया। 'ऑपरेशन सिंदूर' कूटनीतिक रूप से एक असफलता रहा। 26/11 के बाद मनमोहन सिंह ने भारत को 'भारत-पाक' की जोड़ से अलग कर दिया था। पाकिस्तान एक 'दुष्ट राष्ट्र' था, और हम जिम्मेदार शक्ति। लेकिन आज के नाटकीय राष्ट्रवाद में वह वैश्विक सद्भावना कमजोर हो गई है। क्या हम फिर से बॉलीवुड के जुड़वां बन गए हैं, जिन्हें अमेरिका 'पाकिस्तान' के परमाणु हथियारों की सुरक्षा के नाम पर एक साथ नचवा रहा है? या फिर ये अमेरिका के हथियार हैं जो सर्गोधा किनारे की गुफाओं में छिपे हैं? शायद हम भूल जाते हैं कि युद्ध में सिर्फ एक दिन का खर्च भारत के लिए अनुमानित .18 बिलियन है— वह भी केवल लड़ाई पर। आम नागरिकों, परिवारों, श्रमिकों और उत्पादक कंपनियों को होने वाले नुकसान की तो बात ही अलग है। पाकिस्तान भी रोज .3 बिलियन से कम नहीं खर्च कर रहा— अपने ही गरीबों और लाचार जनता को वंचित कर। और इसी बीच, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मिला ढ्ढरूस्न का .1 बिलियन का सहायता पैकेज-जिसने उसकी आतंकवादी गतिविधियों को और बल दे दिया। और जब राष्ट्रीय विमर्श बिगड़ता है, तो हम वही करते हैं जो हमेशा करते आए हैं- संदेशवाहक को दोष दो। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, जिन्हें संघर्ष विराम की घोषणा करनी पड़ी, उन्हें बेरहमी से ट्रोल किया गया। केवल उन्हें ही नहीं- उनकी पत्नी और बेटी को भी ऐसे जहरभरे हमलों का सामना करना पड़ा कि नाली का कीचड़ भी शरमा जाए। यह घिनौना था।

मिस्त्री के बॉस, हमेशा आक्रामक एस. जयशंकर, खामोशी ओढ़ लेते हैं। लेकिन सतह को खुरचो, तो असली समस्या और गहरी है। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन-संभवत: इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति-ने चेताया था- 'राष्ट्रवाद एक बचकानी बीमारी है। यह मानवता का खसरा है।' राष्ट्रवाद, अंधराष्ट्रवाद नहीं है। किसी भी लोकतंत्र को एक मजबूत विरोध-युद्ध संस्कृति की ज़रूरत होती है। भारत को यह संस्कृति गौतम बुद्ध और भगवान कृष्ण से विरासत में मिली है। उसे इसे और तेज करने की जरूरत है। कभी पंचशील की वजह से भारत को नुकसान हुआ, लेकिन यह अमानवीय होने का कारण नहीं हो सकता। 26/11 की मुंबई त्रासदी के बाद, भारत की मजबूत कूटनीति ने पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग-थलग कर दिया था। अब, 'ऑपरेशन सिंदूर' की आड़ में भारत को पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहिए- बातचीत के लिए मजबूर करे, उसे सुधरने पर मजबूर करे, और पूरे भारतराष्ट्र यानी भारतीय उपमहाद्वीप को एक शांति क्षेत्र में बदल दे- सार्क (स्न्रक्रष्ट) का पुनरुद्धार कर। पाकिस्तान, बांग्लादेश और पश्चिम एशिया हथियारों के सौदागरों और विदेशी लालच से तबाह हो चुके हैं। भारत को पूरे क्षेत्र से कहना चाहिए- हथियार छोड़ो, सहानुभूति अपनाओ। अंधराष्ट्रवाद देशभक्ति नहीं है। राष्ट्रवाद नफ़रत या विदेशी-विरोध नहीं है। भारत को संघर्ष की तलाश नहीं करनी चाहिए- लेकिन यदि मजबूर किया जाए, तो तैयार रहना चाहिए। फिर भी, युद्ध केवल हानि लाता है, प्रगति नहीं। बुजुर्गों को युवाओं को याद दिलाना चाहिए- वीरता अक्सर शहीद स्मारकों में खत्म होती है, किसी गहरे अर्थ में नहीं। राष्ट्र निर्माण युद्ध से नहीं, शांति से होता है। उपमहाद्वीप को युद्ध-आधारित अर्थव्यवस्था को अस्वीकार करना होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और पश्चिम एशिया को हथियारों और विदेशी स्वार्थों ने बरबाद कर दिया है। यहां तक कि आतंकवादी भी 'हीरो' बन जाते हैं जब वे युद्ध आधारित व्यापार के लिए काम करते हैं।

■ **मीडिया मैप न्यूज नेटवर्क**

राष्ट्रीय एकता

मैं उस भारत में पला-बढ़ा, जहां 'गंगा-जमुनी तहज़ीब' गर्व की बात थी और 'राष्ट्रीय एकता' एक नारा नहीं, व्यवहारिक सच्चाई थी। आज राष्ट्रवाद को बहुसंख्यकवाद से जोड़ दिया गया है, और 'एकता' का अर्थ केवल प्रभुत्वशाली समुदाय की बात मानने तक सीमित कर दिया गया है।

एक समय था जब अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्में, जो धार्मिक एकता का संदेश देती थीं, टैक्स से मुक्त होती थीं। आज 'द कश्मीर फाइल्स' जैसी फिल्मों पर टैक्स माफ किया जाता है, और उनके बाद थिएटरों में लोग बदला लेने की मांग करते हैं। दुनिया में भारत को मुस्लिम देशों में इज्जत की निगाह से देखा जाता था, क्योंकि भारत को मुसलमान भी अपना देश मानते थे। आज भारत का नाम मुसलमानों पर अत्याचार और इस्लामोफोबिया से जोड़ा जा रहा है।

सांप्रदायिक विभाजन सिर्फ गहराता नहीं जा रहा है, यह हमारे समाज को ज़हरीला बना रहा है और इसे बर्बादी की

ओर ले जा रहा है। इससे उत्पन्न होने वाले परिणाम अनिश्चित और खतरनाक हैं। राष्ट्रीय एकता का दौर समाप्त हो चुका है, हम केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे शासकों में इतनी समझ हो कि वे राष्ट्रीय विघटन का युग शुरू होने से रोक सकें।

महंगाई

यह कहानी केवल हमारे परिवार की नहीं, बल्कि पूरी पीढ़ी की है। मेरे पिता की शादी 1944 में हुई। सिर्फ माँ-पिता और नजदीकी रिश्तेदारों की मौजूदगी में, कुल खर्च लगभग 1500 रुपया। मेरी शादी 25,000 में हुई और मेरे बच्चे की शादी का खर्च 5,00,000 तक पहुँच गया।

तो सवाल है कि दादा-दादी तीस की उम्र तक घर खरीद लेते थे, भाई-बहनों की शादियाँ करा देते थे और परिवार सँभाल लेते थे, जबकि हम पचास की उम्र तक भी एक फ्लैट खरीदने में संघर्ष क्यों कर रहे हैं?

आसान जवाब है- महँगाई।

सच्चा जवाब है- उपभोग।

उनकी शादियाँ एक साड़ी, एक धोती, थोड़ा-सा सोना और लड्डू में पूरी हो जाती थीं। हमारी शादियाँ लाखों में सिर्फ सजावट और फोटोशूट पर खर्च होती हैं। उनके स्कूल सरकारी थे, फीस सालाना 20-100 रुपया। आज 'सामान्य' फीस 2.5 लाख सालाना है।

उनके लिए घर आश्रय था, हमारे लिए क्लब हाउस और स्विमिंग पूल का प्रतीक। वे घर का खाना खाते थे, हम 10,000 रुपया महीने रेस्तरां पर उड़ा देते हैं।

सबसे बड़ा फर्क मानसिकता का है। तुलना से प्रतियोगिता, प्रतियोगिता से आकांक्षा, और आकांक्षा से उपभोग जन्मा। उपभोग ने हमें कर्ज़ में डुबो दिया।

सच यह है- हमारे बुजुर्ग कमी में भी गरिमा से जीते थे। हम अति में भी कर्ज में डूबे हैं। उन्होंने बिना सेल्फी के संपत्ति छोड़ी। हम संपत्ति छोड़ने के बजाय सिर्फ सेल्फियाँ छोड़ रहे हैं। हमें महँगाई ने नहीं, बल्कि हमारी आकांक्षाओं ने हराया।

युद्ध खत्म : चुनाव प्रचार शुरू!

पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश और एकजुटता का माहौल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की एक रैली में आतंकियों को ऐसी सजा देने की बात कही जो 'कल्पना से परे' होगी। विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में सरकार को समर्थन का आश्वासन दिया और आम जनमानस भी सख्त कार्रवाई चाहता था।

डॉ. मुज़फ्फर हुसैन ग़ज़ाली

भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध खत्म करते हुए व्यापार, आवाजाही और सिंधु जल समझौते को भी रोक दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को कुछ तत्वों ने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। मुसलमानों को निशाना बनाया गया, दुकानों और मस्जिदों पर हमले हुए। जबकि पहलगाम में आतंकियों के निशाने पर एक मुसलमान और एक ईसाई थे, जिन्हें स्थानीय मुसलमानों ने अस्पताल पहुंचाया। श्रीनगर के मुसलमानों ने बाजार बंद कर आतंकवाद का विरोध किया। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने हमले की निंदा करते हुए सरकार को समर्थन देने का आश्वासन दिया।

सीमा पर युद्ध जैसे हालात बन गए थे, और इसी बीच सरकार ने जाति आधारित जनगणना की घोषणा कर दी। लेकिन जनता की प्राथमिकता न्याय और जवाबी कार्रवाई थी। सरकार ने 7 मई को रात में 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इस ऑपरेशन का नेतृत्व एयरफोर्स की वरिष्ठ महिला अधिकारी सोफिया कुरैशी ने किया, साथ में थीं विंग कमांडर

भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध खत्म करते हुए व्यापार, आवाजाही और सिंधु जल समझौते को भी रोक दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को कुछ तत्वों ने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। मुसलमानों को निशाना बनाया गया, दुकानों और मस्जिदों पर हमले हुए। जबकि पहलगाम में आतंकियों के निशाने पर एक मुसलमान और एक ईसाई थे, जिन्हें स्थानीय मुसलमानों ने अस्पताल पहुंचाया। श्रीनगर के मुसलमानों ने बाजार बंद कर आतंकवाद का विरोध किया। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने हमले की निंदा करते हुए सरकार को समर्थन देने का आश्वासन दिया।

वोमिका सिंह। यह एक सशक्त प्रतीक था कि भारत की कार्रवाई साम्प्रदायिकता से परे है। हालांकि नफरत का जहर इतना गहरा है कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री और खुद सोफिया कुरैशी को भी सोशल मीडिया ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी लगभग बीस दिन तक सामने नहीं आए। उन्होंने न तो सर्वदलीय बैठक में भाग लिया और न ही सार्वजनिक रूप से बयान दिया। अंतत: 12 मई को उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया।

इस भाषण से पहले देशभर में अनेक सवाल उठाए जा रहे थे- क्या अमेरिका ने युद्धविराम में भूमिका निभाई? क्या चीन पाकिस्तान के साथ था? क्या भारत ने अमेरिका से अनुरोध किया? प्रधानमंत्री का भाषण इन सभी अटकलों के बीच आया और अपेक्षा थी कि वे 'ऑपरेशन सिंदूर' की जानकारी साझा करेंगे।

प्रधानमंत्री ने अमेरिका के मध्यस्थता प्रस्ताव को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि भारत कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा मानता है और किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने पाकिस्तान को चेताया कि अब 'घर में घुसकर मारा जाएगा।' सिंधु जल समझौते पर कहा, 'पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते।'

हालांकि जनता के मन में सवाल रह गए- जब भारत दबाव में नहीं था, तब युद्धविराम क्यों किया गया? ट्रंप ने इसकी घोषणा पहले क्यों की? और भारत ने उसी लाइन को दोहराया क्यों? क्या कोई समझौता हुआ? यदि नहीं, तो मौखिक बातों को स्वीकार करना कितना उचित था? दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इसे अपनी जीत घोषित कर रहे हैं, और पाकिस्तान की ओर से हमले अब भी जारी हैं। इस घटनाक्रम से भाजपा समर्थकों और पत्रकारों तक में सवाल उठने लगे। विदेश सचिव मिस्री को ट्रोल करना यह दर्शाता है कि भाजपा ने एक ऐसी ट्रोल आर्मी तैयार की है जो अब उन्हीं को निशाना बना रही है।

प्रधानमंत्री ने अमेरिका के मध्यस्थता प्रस्ताव को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि भारत कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा मानता है और किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने पाकिस्तान को चेताया कि अब 'घर में घुसकर मारा जाएगा।' सिंधु जल समझौते पर कहा, 'पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते।'

सरकार ने इस प्रतिनिधिमंडल की अगुआई के लिए कांग्रेस के शशि थरूर को चुना, लेकिन बाकी सदस्य भाजपा और सहयोगी दलों से हैं। सपा, टीएमसी और कांग्रेस द्वारा सुझाए गए नामों को नजरअंदाज कर दिया गया।

इस बीच भाजपा ने 10 दिन तक 'तिरंगा यात्रा' निकालने का निर्णय लिया है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का प्रचार किया जाएगा। साथ ही सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों और नाटो देशों से संपर्क करेगा। सरकार ने इस प्रतिनिधिमंडल की अगुआई के लिए कांग्रेस के शशि थरूर को चुना, लेकिन बाकी सदस्य भाजपा और सहयोगी दलों से हैं। सपा, टीएमसी और कांग्रेस द्वारा सुझाए गए नामों को नजरअंदाज कर दिया गया। यह पहल सही दिशा में हो सकती थी यदि सभी दलों को इसमें शामिल किया जाता, लेकिन अब यह भी राजनीति का हिस्सा बन गई है। विपक्ष की भूमिका पर भी प्रश्न उठ रहे हैं- क्या वह इस राष्ट्रीय संकट को राजनीति से ऊपर उठकर देख पाएगा?

अंत में सवाल यही है- क्या हमने ऑपरेशन सिंदूर से अपना लक्ष्य हासिल कर लिया? जवाब आंशिक 'हां' है- हमारी सेना ने जवाब दिया, नेतृत्व में विविधता और साहस दिखा। लेकिन सरकार की राजनीतिक चुप्पी, ट्रोल संस्कृति और विदेश मंत्री के विरोधाभासी बयान ने स्थिति को धुंधला कर दिया है। भाजपा यह सब चुनावी लाभ के लिए भुनाना चाहती थी, लेकिन परिणाम उलट होते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि विपक्ष किस रुख के साथ आगे बढ़ता है- टकराव का या सहयोग का।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

अंग्रेजों पर अमित शाह की अनावश्यक टिप्पणी

पुरानी बहस को फिर से हवा देने वाला है। हालांकि उनके इस बयान के पीछे की मंशा केवल अटकलों पर आधारित हो सकती है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह टिप्पणी आरएसएस के पुराने नारे 'हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान' के अनुरूप है, और संभवत: विचारधारात्मक कट्टरपंथियों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से दी गई है। यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भड़काने का एक राजनीतिक प्रयास लगता है, जिसमें भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी के विरोध में खड़ा किया जा रहा है—जबकि अंग्रेजी एक वैश्विक संपर्क भाषा बन चुकी है।

इसके विपरीत, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक समावेशी और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, 'आज की दुनिया में, अंग्रेजी आपकी मातृभाषा जितनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आत्मविश्वास और रोज़गार देती है। अंग्रेज़ी एक पुल है, बांध नहीं। यह बेड़ियां तोड़ने का साधन है, जंजीर नहीं। बीजेपी-आरएसएस नहीं चाहते कि भारत का गरीब अंग्रेज़ी सीखे क्योंकि उन्हें डर है कि वह सशक्त हो जाएगा और बराबरी की मांग करेगा।'

राहुल गांधी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी भारतीय भाषाओं का अपना सांस्कृतिक महत्व है, लेकिन हर बच्चे को अंग्रेज़ी सिखाई जानी चाहिए ताकि वह आत्मविश्वासी, प्रतिस्पर्धी और वैश्विक स्तर पर जुड़ा हुआ भारत बना सके।

यह बहस नई नहीं है। 1960 के दशक में समाजवादी नेताओं ने भी अंग्रेज़ी पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन विशेष रूप से तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों के तीव्र विरोध ने यह सुनिश्चित किया कि हिंदी थोपे जाने की नीति न चले। अंतत: तीन-भाषा सूत्र एक समझौते के रूप में उभरा।

महात्मा गांधी ने भी इस विषय पर 1921 में यंग इंडिया में लिखा था- 'मैं चाहता हूं कि हमारे युवक और युवतियां जितनी चाहें अंग्रेज़ी या अन्य विदेशी भाषाएं सीखें और अपने ज्ञान का लाभ भारत और विश्व को दें, जैसे बोस, रे या टैगोर ने किया। लेकिन मैं यह कभी नहीं चाहूंगा कि कोई भी भारतीय अपनी मातृभाषा पर शर्म महसूस करे।'

गांधी का दृष्टिकोण समावेशी और

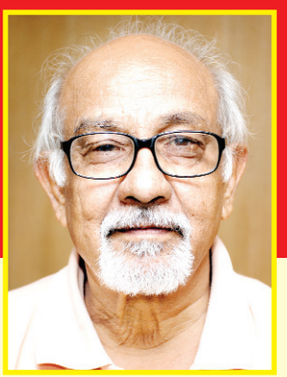

डॉ. सतीश मिश्रा

♦♦

विडंबना यह है कि 2025 में, जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल संवाद दुनिया को नया रूप दे रहे हैं, भाषा को राजनीतिक फुटबॉल बनाना पीछे जाने जैसा लगता है। भाषा जुड़ाव का माध्यम है, देशभक्ति का पैमाना नहीं। भारत की आर्थिक शक्ति और वैश्विक प्रतिष्ठा में उसका अंग्रेज़ी जानने वाला कार्यबल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं चीन ने कभी अंग्रेज़ी को लेकर शर्म की भावना नहीं फैलाई—उनके कई पेशेवर अमेरिका और ब्रिटेन में शिक्षित हैं, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ने व्यावहारिक भाषा नीति अपनाई। एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शाह ने कहा, 'हमारी भाषाएं हमारी संस्कृति के आभूषण हैं। इनके बिना हम सच्चे भारतीय नहीं रह सकते।'

♦♦

दूरदर्शी था, जो आज कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही विभाजनकारी सोच के विपरीत है। विडंबना यह है कि 2025 में, जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल संवाद दुनिया को नया रूप दे रहे हैं, भाषा को राजनीतिक फुटबॉल बनाना पीछे जाने जैसा लगता है। भाषा जुड़ाव का माध्यम है, देशभक्ति का पैमाना नहीं। भारत की आर्थिक शक्ति और वैश्विक प्रतिष्ठा में उसका अंग्रेज़ी जानने वाला कार्यबल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं चीन ने कभी अंग्रेज़ी को लेकर शर्म की भावना नहीं फैलाई—उनके कई पेशेवर अमेरिका और ब्रिटेन में शिक्षित हैं, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ने व्यावहारिक भाषा नीति अपनाई।

एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शाह ने कहा, 'हमारी भाषाएं हमारी संस्कृति के आभूषण हैं। इनके बिना हम सच्चे भारतीय नहीं रह सकते।' यह बात भाषायी शुद्धतावादियों को भले ही भायी हो, लेकिन उनके बयान का समय सवाल खड़े करता है। दक्षिणी राज्य, विशेष रूप से तमिलनाडु, लगातार बीजेपी की तीन-भाषा नीति का विरोध करते रहे हैं और इसे हिंदी थोपने की छुपी हुई कोशिश मानते हैं।

शाह के बयान बंगाल के मार्क्सवादी विचारक प्रमोद दासगुप्त की उस दलील की याद दिलाते हैं, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा से अंग्रेज़ी हटाने का अभियान चलाया था। हिमांशु बिमल मजूमदार आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह दावा किया गया कि शुरुआती वर्षों में दो भाषाएं सीखना 'अवैज्ञानिक' है। वाम मोर्चा ने कक्षा 6 तक अंग्रेज़ी शिक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि अंग्रेज़ी उच्चवर्गीयता को बढ़ावा देती है और ड्रॉपआउट दर को बढ़ाती है।

परिणाम विनाशकारी थे, बंगाल की एक पूरी पीढ़ी अंग्रेज़ी में संवाद करने में पिछड़ गई। शहरी माता-पिता ने अपने बच्चों को अंग्रेज़ी-माध्यम निजी स्कूलों में भेजना शुरू कर दिया, जिससे गहरी असमानताएं पैदा हुईं। बाद में मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के कार्यकाल में कक्षा एक से अंग्रेज़ी वापस लाई गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिक्षक खुद उस पीढ़ी से थे जिन्हें अंग्रेज़ी नहीं सिखाई गई थी, इसलिए वे इसे प्रभावी ढंग से पढ़ा भी नहीं सके। वामपंथी दल को सत्ता से बाहर हुए 14 साल हो चुके हैं, लेकिन वह गलत भाषा नीति आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही।

अमि शाह की स्थिति और भी विरोधाभासी तब लगती है जब प्रधानमंत्री मोदी खुद अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अंग्रेज़ी में बोलते हैं और सरकार शशि थरूर जैसे नेताओं पर भरोसा करती है कि वे अंग्रेज़ी भाषी देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करें।

वैश्विक जुड़ाव और घरेलू भाषण के बीच यह विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी-आरएसएस की दोहरी सोच को उजागर करता है। भाषाओं-अंग्रेज़ी सहित-को उच्चवर्गीयता या राष्ट्रवाद का प्रतीक नहीं बनाना चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है, लेकिन उस साधन की कीमत पर नहीं जो भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ता है और सामाजिक तरक्की का मार्ग प्रशस्त करता है।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'भारत में 97% लोग 22 संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं में से किसी एक को मातृभाषा के रूप में उपयोग करते हैं। यही है हमारे महान राष्ट्र की 'विविधता में एकता'। अमित शाह, पीएम मोदी और उनके साथी इसे कभी नहीं समझ सकते।' उनका यह बयान इस बात को रेखांकित करता है कि भाषायी गौरव को राजनीतिक विचारधारा के साथ मिलाना कितना खतरनाक हो सकता है।

अमि शाह की स्थिति और भी विरोधाभासी तब लगती है जब प्रधानमंत्री मोदी खुद अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अंग्रेज़ी में बोलते हैं और सरकार शशि थरूर जैसे नेताओं पर भरोसा करती है कि वे अंग्रेज़ी भाषी देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करें। वैश्विक जुड़ाव और घरेलू भाषण के बीच यह विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी-आरएसएस की दोहरी सोच को उजागर करता है। भाषाओं-अंग्रेज़ी सहित-को उच्चवर्गीयता या राष्ट्रवाद का प्रतीक नहीं बनाना चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है, लेकिन उस साधन की कीमत पर नहीं जो भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ता है और सामाजिक तरक्की का मार्ग प्रशस्त करता है। एक बहुभाषी भारत, एक मजबूत भारत है, कमजोर नहीं।

अमित शाह को इतिहास से सबक लेना चाहिए और भविष्य की व्यावहारिक ज़रूरतों को समझना चाहिए। लोगों को अंग्रेज़ी बोलने के लिए शर्मिंदा करने की बजाय, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बच्चे को, उसकी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, अपनी मातृभाषा और इस अवसरों की वैश्विक भाषा-अंग्रेज़ी- दोनों में दक्षता प्राप्त करने का समान अवसर मिले।

(लेखक मीडिया मैप के संयुक्त संपादक हैं)

वक्फ बिल से बीजेपी का जनाधार होगा प्रभावित

प्रोफेसर प्रदीप माथुर

वक्फ संशोधन बिल, जिसे संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया, मोदी सरकार के लिए तत्काल कोई खतरा उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन यह निश्चित रूप से देश के राजनीतिक आकाश पर बीजेपी की प्रभुत्वता के अंत का संकेत देता है। बीजेपी नेतृत्व ने मुसलमान संगठनों और कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद इस विवादास्पद उपाय के लिए समर्थन जुटाने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन यह जन मानस की मानसिकता को समझने में असफल रहा है, जो अंतत: मायने रखती है। कारण यह है कि बीजेपी नेताओं को उस भारतीय मतदाता की चिंताओं, भय और खतरे की भावना का पता नहीं है, जो गरीब भारतीयों के अवचेतन मन में निहित हैं। आइए हम इस अवचेतन मन में झांकने की कोशिश करें।

आर्थिक उदारीकरण के पूर्व काल में भारत के प्रमुख अर्थशास्त्रियों में से एक प्रोफेसर एम.वी. माथुर थे। 1974 में चंडीगढ़ में एक सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आए हुए प्रोफेसर माथुर से एक युवा रिपोर्टर के रूप में, मुझे उनका साक्षात्कार करने का अवसर मिला। वह समय था जब हमारा देश हरित क्रांति से गुजर रहा था और 1960 के दशक के अंतिम भाग के निराशाजनक वर्षों के बाद, जब देश में अकाल और संयुक्त राज्य अमेरिका से पीएल 480 की अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा था, हर जगह आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति की उम्मीदें फैली हुई थीं। जैसे ही हमने विशेष साक्षात्कार शुरू किया, मैंने उनसे पूछा कि चूंकि हरित क्रांति बहुत सारा धन उत्पन्न कर रही थी, तो आपके अनुसार यह धन सबसे अच्छा कहां निवेश किया जाना चाहिए ताकि हमारे देश का समग्र विकास तेजी से हो सके।

मैंने उम्मीद की थी कि यह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उद्योग और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के बारे में कहेंगे, क्योंकि यही वे क्षेत्र थे जिनमें पश्चिमी दुनिया, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हावी थी, नहीं चाहती थी कि हम निवेश करें। अपनी प्रभुत्वता बनाए रखने के लिए, वे चाहते थे कि भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बना रहे और नेहरू को इस परत्ति से नाराज थे कि उन्होंने देश को औद्योगिकीकरण के रास्ते पर डाल दिया था।

मेरे आश्चर्य के लिए, प्रोफेसर एम.वी. माथुर ने कहा कि देश में एक बड़ी आवास संकट है और हमें अपनी संसाधनों को समाज के सभी वर्गों के लिए आवास निर्माण की दिशा में लगाना चाहिए। आवास निर्माण उद्योगों जैसे सीमेंट, स्टील और सैनिटरी वेयर को बढ़ावा देगा, उन्होंने अपने तर्क का समर्थन करते हुए कहा। 'यह तो ठीक है सर, लेकिन भारतीयों के पास स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, परिवहन और एक अच्छा जीवन स्तर जैसे आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, तो वे घर खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे ?' मैंने पूछा। जो बात इस अर्थशास्त्री ने कही, उसने मुझे और भी चौंका दिया। उन्होंने कहा कि भारतीयों के पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं हो सकते, लेकिन वे हमेशा दो चीजों के लिए संसाधन जुटा सकते हैं— घर खरीदने और शादी समारोह आयोजित करने के लिए।

मैंने अपनी रिपोर्ट फाइल की, लेकिन जो उन्होंने कहा, उस पर सोचता रहा। मैंने चारों ओर देखा और अपने सहयोगियों, दोस्तों और परिवार के सदस्यों में अपनी खुद की एक घर की चाहत को महसूस किया, चाहे वह कितने भी साधारण क्यों न हों। मैंने यह भी देखा कि जिन लोगों के पास अपना घर था, उनके चेहरे पर खुशी थी। जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि किसी का अपना घर होना लोगों को विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, जहाँ की पीढ़ियों को मध्यकाल में आक्रमणकारी सेनाओं के हमलों, लूटपाट और विस्थापन का सामना करना पड़ा था, एक अद्वितीय आत्मविश्वास और आत्म-निर्भरता का अहसास दिलाता है। किसी का खुद का घर या जमीन उसकी अस्तित्व की आवश्यकता है और जीवित रहने की सबसे अच्छी गारंटी है। चौधरी चरण सिंह और लालू प्रसाद यादव की राजनीति इसका प्रमाण है। उनके द्वारा शुरू की गई ज़मीन सुधारों ने भूमिहीनों को लाभ पहुंचाया और उन्होंने इन नेताओं की पूजा भगवान की तरह की।

दुर्भाग्यवश, उत्तर भारतीय मानसिकता में निहित इस बुनियादी गुण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेतृत्व किए गए गुजराती लॉबी न तो जानती है और न ही इसे समझने के लिए तैयार है। वे एक पैसे-केंद्रित व्यापार संस्कृति के प्रवर्तक हैं, और उन्हें यह समझ में नहीं आता कि कोई भी नकद सब्सिडी या मुफ्त राशन इस अस्तित्व संबंधी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता। चाहे जितना भी अच्छा इरादा हो, कोई भी उपाय जो लोगों को अपनी ज़मीन से वंचित करने का खतरा उत्पन्न करता है। पहले उन्होंने तीन कृषि बिल लाए थे, जिन्हें भले ही वापस ले लिया गया हो, लेकिन इसने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पार्टी के जनाधार को कमजोर किया और 2024 के चुनावों में उन्हें भारी नुकसान हुआ।

यदि प्रधानमंत्री मोदी और उनके आसपास के लोग यह सोचते हैं कि वक्फ बिल केवल मुसलमानों को प्रभावित करेगा, जो उनके वोट बैंक में नहीं आते, तो वे गलत हैं। यदि वे सोचते हैं कि हिन्दू इससे खुश होंगे, तो वे फिर से गलत हैं। सरकार के इरादों या उद्देश्य चाहे जो भी हों, साधारण आदमी के लिए संदेश यह होगा कि सरकार उन्हें उनकी ज़मीन से वंचित करना चाहती है, जो उनकी सुरक्षित जीवित रहने की गारंटी है। और यह संदेश मुसलमानों, दलित हिन्दुओं और सभी वर्गों के गरीबों के लिए होगा, जो अपने ज़मीन से उखाड़े जाने के डर के साथ असुरक्षित जीवन जी रहे हैं। इससे सभी समुदायों के गरीब वर्गों का बीजेपी से विलगाव होगा, जिसे कोई भी आर्थिक सब्सिडी या सांप्रदायिक प्रचार दूर नहीं कर पाएगा।

भारत ने जापान को वैश्विक GDP रैंकिंग में पीछे छोड़ा

शिवाजी सरकार

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सरकार को रिकॉर्ड 2.69 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया है, जबकि पिछले साल यह 2.1 लाख करोड़ था। यह बढ़ोतरी मुख्यत: डॉलर की बिक्री, विदेशी मुद्रा लाभ और ब्याज आय में वृद्धि के कारण हुई है। यह तब हुआ है जब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अनुमान लगाया है कि भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

यह डिविडेंड केंद्र सरकार के 2025 के बजट अनुमान (2.56 लाख करोड़) से भी अधिक है और इससे सरकार को राजकोषीय घाटा और उधारी कम करने में मदद मिलेगी। यह 2011–12 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड है, जब यह केवल 15,009 करोड़ था और 2013–14 में 33,010 करोड़ हुआ था। नोटबंदी के दौरान 2016–17 में 65,876 करोड़ और 2018–19 में 1,76,051 करोड़ रहा था। 2019 में यह 40,000 करोड़ तक घटा, लेकिन 2020–21 में 99,122 करोड़ तक फिर बढ़ गया।

भारत ने वैश्विक मंच पर एक और बड़ी छलांग लगाई है। भारत की नाममात्र GDP .4.187 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जिससे उसने जापान (.4.186 ट्रिलियन) को पीछे छोड़ दिया है।

IMF के वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक के अनुसार, भारत इस वर्ष 6.3% की दर से वृद्धि करेगा, जो कि पहले के 6.5% अनुमान से थोड़ा कम है। इसके विपरीत, जापान की विकास दर को घटाकर 0.6% कर दिया गया है, जो पहले जनवरी में 1.1% थी। यह व्यापार तनाव और जनसांख्यिकीय चुनौतियों के कारण हुआ है।

हालांकि भारत और जापान के बीच प्रति व्यक्ति आय में लगभग 12 गुना का अंतर है, फिर भी भारत की विकास दर से यह संभावना जताई जा रही है कि 2027 तक वह जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।

डिविडेंड की इस कहानी में एक चेतावनी भी है। RBI ने एक साथ यह भी बताया कि विदेशी मुद्रा भंडार में .4.9 बिलियन की गिरावट आई है, जो कि सितम्बर 2024 के रिकॉर्ड .704 बिलियन से घटकर अब .६85.7 बिलियन रह गया है। रिपोर्ट के अनुसार, मुद्रा स्थिरता बनाए रखने के लिए RBI

भारत ने वैश्विक मंच पर एक और बड़ी छलांग लगाई है। भारत की नाममात्र GDP .4.187 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जिससे उसने जापान (.4.186 ट्रिलियन) को पीछे छोड़ दिया है। IMF के वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक के अनुसार, भारत इस वर्ष 6.3% की दर से वृद्धि करेगा, जो कि पहले के 6.5% अनुमान से थोड़ा कम है। इसके विपरीत, जापान की विकास दर को घटाकर 0.6% कर दिया गया है, जो पहले जनवरी में 1.1% थी। यह व्यापार तनाव और जनसांख्यिकीय चुनौतियों के कारण हुआ है। हालांकि भारत और जापान के बीच प्रति व्यक्ति आय में लगभग 12 गुना का अंतर है, फिर भी भारत की विकास दर से यह संभावना जताई जा रही है कि 2027 तक वह जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। डिविडेंड की इस कहानी में एक चेतावनी भी है। RBI ने एक साथ यह भी बताया कि विदेशी मुद्रा भंडार में .4.9 बिलियन की गिरावट आई है, जो कि सितम्बर 2024 के रिकॉर्ड .704 बिलियन से घटकर अब .685.7 बिलियन रह गया है। रिपोर्ट के अनुसार, मुद्रा स्थिरता बनाए रखने के लिए RBI ने बड़ी मात्रा में डॉलर बेचे हैं।

ने बड़ी मात्रा में डॉलर बेचे हैं।

यह असाधारण अधिशेष डिविडेंड मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा बाजार में RBI के आक्रामक हस्तक्षेप का परिणाम है। जनवरी 2025 में, RBI एशिया के सभी देशों में सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा विक्रेता बन गया था।

इस डिविडेंड ट्रांसफर से वास्तविक प्राप्तियां बजट लक्ष्य से कहीं अधिक हो गई हैं- जो आम चुनावों से पहले सरकार के लिए एक अच्छी स्थिति बनाती है। भंडार में यह गिरावट मुख्य रूप से सोने के भंडार में कमी के कारण हुई है, हालांकि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में थोड़ी वृद्धि हुई है। RBI ने पहले कम दरों पर सोना खरीदा था जिससे अब उसे फायदा हुआ है क्योंकि जनवरी से सोने की कीमतों में तेज वृद्धि हुई है।

विश्व स्तर पर सोने की कीमतों में उछाल देखा गया है, 2024-25 में अनुमानित 39.75% रिटर्न के साथ-जो पिछले 40 वर्षों में सबसे अधिक है। डॉलर के कमजोर होने से सोना गैर-अमेरिकी खरीदारों के लिए सस्ता हुआ, जिससे मांग और कीमत दोनों बढ़े। केंद्रीय बैंकों की खरीदारी से भी सोने की कीमतें बढ़ीं। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2025 के अंत तक सोने की कीमत .3,700 प्रति औंस तक जा सकती है। RBI के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक वर्ष में देश के विशेष आहरण अधिकार (SDRs) .43 मिलियन घटकर .18.490 बिलियन हो गए हैं। IMF में भारत की आरक्षित स्थिति भी .3 मिलियन घटकर .4.371 बिलियन रह गई है। इन परिसंपत्तियों पर यूरो, पाउंड और येन जैसी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की विनिमय दरों का प्रभाव पड़ता है। सोने के भंडार में एक सप्ताह पहले .4.52 बिलियन की वृद्धि के बाद .5.121 बिलियन की भारी गिरावट देखी गई। यह अचानक आए उतार-चढ़ाव का संकेत देता है।

इस बीच, रुपया 79 पैसे मजबूत हुआ है और यह 86 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, क्योंकि डॉलर 2023 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। यह गिरावट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक जून से यूरोपीय यूनियन से आयात पर 50% टैरिफ और अमेरिका के बाहर बने एप्पल आइफोन्स पर 25% टैरिफ लगाने के प्रस्ताव के बाद आई। डिविडेंड का यह फायदा इस वैश्विक आर्थिक बदलाव में भारत की मजबूत स्थिति को भी दर्शाता है। मजबूत मूलभूत तत्वों और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच लचीलापन दिखाते हुए भारत अब एशिया और उससे परे आर्थिक शक्ति संतुलन को पुन: परिभाषित कर रहा है। IMF का अनुमान है कि 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था .6.8 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी- जो कि जर्मनी से 20% और जापान से एक-तिहाई अधिक होगी।

ऐसे में RBI की भूमिका उम्मीदों को नई दिशा देती है। हालांकि विदेशी मुद्रा बाजार की स्थिति इतनी सरल नहीं है जितनी दर्शायी जा रही है। शेयर बाजार में भी कुछ वृद्धि (979 अंक) के बावजूद 19 मई से 25 मई के बीच 2587 अंकों की भारी गिरावट आई है, जिसका कारण घरेलू मुद्दों और वैश्विक बाजार में उठापटक है।

अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच, डॉलर की सकल बिक्री .371.6 बिलियन तक पहुंच गई, जो कि FY.24 के .153 विलियन से दोगुनी से भी अधिक है। इन बड़े हस्तक्षेपों ने न केवल रुपये की अस्थिरता को नियंत्रित किया बल्कि विदेशी मुद्रा लेन-देन से भारी लाभ भी हुआ, जिससे RBI का अधिशेष बढ़ा।

RBI ने रुपये आधारित प्रतिभूतियों से भी अधिक कमाई की। मार्च 2025 तक इन प्रतिभूतियों में उसका निवेश 1.95 लाख करोड़ बढ़कर 15.6 लाख करोड़ हो गया। हालांकि सरकारी बॉन्ड यील्ड में गिरावट से मार्क-टू-मार्केट लाभ कम हुआ, फिर भी कुल ब्याज आय में लगातार वृद्धि हुई। 'कंटिंजेंट रिस्क बफर' (CRB), जो भविष्य के जोखिमों से सुरक्षा के लिए रखा जाता है, उसे RBI की बैलेंस शीट के 4.5% से 7.5% के दायरे में बनाए रखा गया, जैसा कि केंद्रीय बोर्ड ने अनुशंसा की थी।

हस्तांतरित अधिशेष की गणना संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचे (ECF) के तहत की गई, जिसे 15 मई 2025 को RBI के केंद्रीय बोर्ड की बैठक में अनुमोदित किया गया था।

SBI की रिपोर्ट में भी RBI की सतर्क वित्तीय रणनीति को रेखांकित किया गया है। हालांकि अंतिम डिविडेंड 2.7 लाख करोड़ है, SBI का अनुमान है कि अगर RBI ने CRB न बढ़ाया होता तो यह 3.5 लाख करोड़ से अधिक हो सकता था। यह कदम आर्थिक झटकों से सुरक्षा की दृष्टि से उठाया गया और यह RBI की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की विवेकपूर्ण नीति को दर्शाता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया शिक्षक है)

मोदी सरकार की 'बैलेंसिंग एक्ट' की बात महज दिखावा

मीडिया मैप न्यूज़ नेटवर्क

13 जून को ईरान पर इज़राइल के मिसाइल हमले ने न केवल वैश्विक युद्ध के काले बादलों को और निकट ला दिया है, बल्कि कई छिपी हुई सच्चाइयों और तथ्यों को भी उजागर कर दिया है। इसमें भारत द्वारा अमेरिका समर्थित इज़राइल का पूर्ण समर्थन और साथ ही 'संतुलन बनाने' का दिखावा करना शामिल है।

अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत की स्वतंत्र नीति या कार्रवाई का मोदी सरकार का दावा तब उजागर हो गया जब भारत ने एक बार फिर ईरान-इज़राइल संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र में मतदान से परहेज़ किया। शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के उस बयान से दूरी बनाना, जिसमें इज़राइल के ईरान पर हमले की निंदा की गई थी, इस बात की पुष्टि करता है।

चीन की अध्यक्षता वाले एससीओ ने एक बयान जारी कर कहा कि उसके सदस्य देश ईरान-इज़राइल तनाव को लेकर 'गंभीर चिंता' व्यक्त करते हैं और ईरानी क्षेत्र पर इज़राइल द्वारा किए गए सैन्य हमलों की 'कड़ी निंदा' करते हैं।

तेहरान पर इज़राइल के शुरुआती हमलों के बाद, भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची से फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने 'घटनाक्रम को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की गहरी चिंता' व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के अनुसार, जयशंकर ने 'तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचने और जल्द से जल्द कूटनीति की ओर लौटने' का आग्रह किया। मंत्रालय ने शुक्रवार को एक अलग बयान में भी अपनी चिंता व्यक्त की थी।

'हम स्थिति पर करीबी नजर रख रहे हैं, जिसमें परमाणु स्थलों पर हमलों से संबंधित रिपोर्ट भी शामिल हैं' बयान में कहा गया। दोनों पक्षों से संवाद और कूटनीति के मौजूदा माध्यमों का उपयोग करने की अपील की गई ताकि 'स्थिति को शांत करने की दिशा में काम हो सके।' बयान में यह भी कहा गया कि 'भारत दोनों देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और घनिष्ठ संबंध रखता है और हरसंभव सहायता देने को तैयार है।'

जहां भारत यह दावा करता रहा है कि वह ईरान के चाबहार बंदरगाह को मध्य एशिया और अफगानिस्तान के लिए अपने निर्यात द्वार के रूप में विकसित कर रहा है, वहीं अमेरिका के दबाव में इस परियोजना की प्रगति बेहद धीमी रही है। इसके उलट भारत और इज़राइल के बीच व्यापार-खासकर रक्षा उपकरणों का- हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है। भारत इज़राइल का सबसे बड़ा हथियार

अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत की स्वतंत्र नीति या कार्रवाई का मोदी सरकार का दावा तब उजागर हो गया जब भारत ने एक बार फिर ईरान-इज़राइल संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र में मतदान से परहेज़ किया। शंघाई सहयोग संगठन (एस्टह) के उस बयान से दूरी बनाना, जिसमें इज़राइल के ईरान पर हमले की निंदा की गई थी, इस बात की पुष्टि करता है। चीन की अध्यक्षता वाले एससीओ ने एक बयान जारी कर कहा कि उसके सदस्य देश ईरान-इज़राइल तनाव को लेकर 'गंभीर चिंता' व्यक्त करते हैं और ईरानी क्षेत्र पर इज़राइल द्वारा किए गए सैन्य हमलों की 'कड़ी निंदा' करते हैं। तेहरान पर इज़राइल के शुरुआती हमलों के बाद, भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची से फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने 'घटनाक्रम को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की गहरी चिंता' व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के अनुसार, जयशंकर ने 'तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचने और जल्द से जल्द कूटनीति की ओर लौटने' का आग्रह किया। मंत्रालय ने शुक्रवार को एक अलग बयान में भी अपनी चिंता व्यक्त की थी।

निर्यात बाजार बन गया है और हालिया जांच में सामने आया है कि भारत ने पिछले साल गाजा युद्ध के दौरान इज़राइल को रॉकेट और विस्फोटक बेचे थे।

SCO के बयान से खुद को अलग करने से एक दिन पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से परहेज़ किया जिसमें गाजा में 'तत्काल, बिना शर्त और स्थायी' युद्धविराम की मांग की गई थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत का यह रुख दरअसल अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की उसकी मंशा से प्रभावित था, विशेष रूप से उस व्यापार समझौते की पृष्ठभूमि में जिसे नई दिल्ली जुलाई की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर प्रस्तावित 27% टैरिफ से पहले अंतिम रूप देना चाहती है।

दरअसल, भारत की फिलिस्तीन नीति में बदलाव की शुरुआत 2015 के मध्य में हुई थी, जब जुलाई में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में उस प्रस्ताव पर मतदान से परहेज़ किया था जिसमें इज़राइल पर 2014 के गाजा युद्ध (जिसे इज़राइल ने 'ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज' नाम दिया था) के दौरान युद्ध अपराधों का आरोप लगाया गया था। महज एक साल पहले मोदी सरकार ने एक ऐसे प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था जो इज़राइल की आलोचना करता था। इसी तरह भारत ने येरुशलम के संदर्भ में यूनेस्को में भी अपना रुख बदला। अप्रैल 2016 में, भारत ने बहुसंख्यक के साथ जाकर अरब समर्थित प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था जिसमें इस्लामिक दावों को मान्यता दी गई थी और यहूदी इतिहास या येरुशलम में इस्लाम से पहले मौजूद यहूदी मंदिरों का कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन बाद में 13 अक्टूबर 2016 और 2 मई 2017 के दो वोटिंग में भारत ने मतदान से परहेज़ किया, जो इसकी पूर्व नीति से एक स्पष्ट विचलन था।

यह वह समय था जब इज़राइल-फिलिस्तीन मुद्दे को अलग-अलग देखने की नीति की शुरुआत हुई, जो तब साफ हो गई जब प्रधानमंत्री मोदी ने इज़राइल तो गए लेकिन रामल्ला (फिलिस्तीन) नहीं गए।

अब जब भारत और इज़राइल के बीच संबंध पिछले आठ वर्षों में मजबूत और गहरे हो गए हैं, तो संभवत: अब समय आ गया है कि भारत एक नई भूमिका निभाए। दरअसल, भाजपा के पूर्व अवतार भारतीय जनसंघ और हिंदू महासभा सहित दक्षिणपंथी संगठन एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) हमेशा से इज़राइल के प्रबल समर्थक रहे हैं और भारतीय सरकार से यहूदी राष्ट्र को पूर्ण राजनयिक मान्यता देने की मांग करते रहे हैं।

दरअसल, भाजपा के पूर्व अवतार भारतीय जनसंघ और हिंदू महासभा सहित दक्षिणपंथी संगठन एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) हमेशा से इज़राइल के प्रबल समर्थक रहे हैं और भारतीय सरकार से यहूदी राष्ट्र को पूर्ण राजनयिक मान्यता देने की मांग करते रहे हैं।

जनसंघ, प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की इज़राइल नीति का सबसे बड़ा आलोचक था। जनसंघ का मानना था कि कांग्रेस की घरेलू और विदेश नीति मुस्लिम अल्पसंख्यकों को तुष्ट करने वाली है और यह कि कांग्रेस देश के भीतर मुस्लिम-समर्थक और बाहर अरब-समर्थक है।

जनसंघ, प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की इज़राइल नीति का सबसे बड़ा आलोचक था। जनसंघ का मानना था कि कांग्रेस की घरेलू और विदेश नीति मुस्लिम अल्पसंख्यकों को तुष्ट करने वाली है और यह कि कांग्रेस देश के भीतर मुस्लिम-समर्थक और बाहर अरब-समर्थक है।

1952 के पहले आम चुनाव में जनसंघ के घोषणापत्र में पार्टी की हिंदुत्ववादी सोच झलकती है, जिसमें कहा गया था कि धर्मनिरपेक्षता 'जैसा कि देश में व्याख्यायित की जाती है, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का एक मोहक रूप है।' कथित धर्मनिरपेक्ष संयुक्त राष्ट्रवाद को न तो राष्ट्रवाद और न ही धर्मनिरपेक्षता बताया गया, बल्कि उसे ऐसे लोगों के सांप्रदायिक समझौते का परिणाम कहा गया जो देश के प्रति अपनी वफादारी के बदले में कीमत मांगते हैं। इसी भावना को प्रतिबिंबित करते हुए, 23 दिसम्बर 1953 को लोकसभा में एक जनसंघ सांसद ने यह मांग की थी कि मुसलमानों को 'सेना, वायु सेना और पुलिस में नहीं लिया जाना चाहिए और उन्हें किसी भी प्रमुख पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें मंत्रियों के अधिकारी भी शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की सीमा से सौ मील की दूरी तक उन लोगों को हटा देना चाहिए जिनकी पाकिस्तान की ओर झुकाव हो सकता है।'

यह आम धारणा रही है कि दक्षिणपंथी पार्टियां, विशेष रूप से जनसंघ और उसके उत्तराधिकारी भाजपा, इज़राइल समर्थक रही हैं क्योंकि वे मुस्लिम विरोधी हैं। जनसंघ की तरह भाजपा ने मुस्लिम अरब राज्यों के प्रति संदेह रखा और उनके विरोधी इज़राइल को 'भारत का संभावित सहयोगी' माना। यह 1998 में तब दिखा जब भाजपा-नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सत्ता में आई। 2004 तक एनडीए सरकार के छह वर्षों में भारत-इज़राइल द्विपक्षीय संबंध गहरे और मजबूत हुए।

तीन वर्षों के संकोच के बाद, मोदी ने अपने पूर्ववर्तियों की परंपरा को तोड़ते हुए जुलाई 2017 में इज़राइल की यात्रा की- किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली आधिकारिक यात्रा थी। प्रधानमंत्री मोदी 4 जुलाई 2017 को इज़राइल पहुंचे। इस यात्रा का महत्व इस बात से स्पष्ट था कि दोनों पक्षों ने अपने रिश्तों की गर्मजोशी और मित्रता को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इज़राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगभग पूरी यात्रा के दौरान मोदी के साथ रहे, जबकि मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत मॉडर्न यहूदी राष्ट्रवाद के जनक थियोडोर हर्ज़ल को श्रद्धांजलि अर्पित करने से की - जो कि कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था।

इससे मोदी सरकार ने फिलिस्तीन और इज़राइल मुद्दों को अलग-अलग देखने की नीति पर निर्णायक कदम उठा लिया। इज़राइल यात्रा से पहले मोदी ने मार्च 2017 में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास की नई दिल्ली में मेज़बानी की थी। अब इज़राइल द्वारा ईरान पर आक्रमण और उस पर भारत की मौजूदा चुप्पी यह साफ दर्शाती है कि भारत ज़ायनिज़्म का डि-फैक्टो (वास्तविक) समर्थक बन चुका है, भले ही अभी तक वह उसका डि-ज्यूर (कानूनी) सदस्य न बना हो। आगामी दिनों और हफ्तों में भारत की विदेश नीति की दिशा और अधिक स्पष्ट और विशिष्ट हो जाएगी।

हमारी स्वास्थ्य मुहिम सिर्फ तेल नहीं आजीविका भी जला सकती है

शिवाजी सरकार

भारत की मोटापे से लड़ाई अब अस्पतालों या जिम में नहीं, बल्कि आपके मोहल्ले के समोसे या जलेबी की दुकान की दीवारों पर लड़ी जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का एक नया निर्देश केंद्र सरकार के कार्यालयों से कहता है कि वे 'तेल और चीनी बोर्ड' लगाएं—जो कर्मचारियों को डीप-फ्राइड और मीठे स्नैक्स के खतरों से आगाह करें।

मकसद नेक है : स्वस्थ खाने की आदतें बढ़ाना, लेकिन इसका एक अनचाहा असर हो सकता है—भारत के विशाल असंगठित खाद्य क्षेत्र के लिए यह तबाही जैसा साबित हो सकता है। यह वह अर्थव्यवस्था है जो समोसे, पकौड़े, जलेबी और भांति, हलवाई, मयारा और मोदक जैसे कारीगरों की मेहनत पर चलती है—जो भले ही जीडीपी के आंकड़ों में न दिखें, पर रोज करोड़ों को खाना खिलाते हैं।

तवे से तंगी तक : एक आर्थिक झटका, यह सिर्फ खानपान की आदतों में बदलाव नहीं, बल्कि एक आर्थिक झटका है। भारत की असंगठित खाद्य अर्थव्यवस्था का अनुमानित मूल्य 3 से 5 लाख करोड़ के बीच है। यह दिल्ली के सरोजिनी नगर से लेकर पटना के गांधी मैदान, कोलकाता के गरर माथ से केरल के समुद्र तटों तक फैली हुई है। प्रतिदिन लगभग 6 करोड़ समोसे बिकते हैं, जो एक हाइपरलोकल सप्लाई चेन से बनते हैं—जिसमें किसान, आटा चक्की वाले, तेल रिफाइनर, ठेलेवाले और कई अन्य शामिल हैं।

अब इसमें पकौड़े, वड़ा पाव, प्याज कचौरी, जलेबी और मिठाइयां जोड़ दें, तो यह एक मजबूत, विकेन्द्रीकृत खाद्य तंत्र बनता है—ताजा, सस्ता और बिना प्रिज़रवेटिव वाला। सिर्फ दशहरा 2023 में, अहमदाबाद में 17 लाख किलो फाफड़ा-जलेबी खाई गई, जिससे एक दिन में लगभग 175 करोड़ की बिक्री हुई—जो कई टेक स्टार्टअप्स की शुरुआती फंडिंग से भी ज्यादा है। फिर भी, जहां पैकेज्ड फूड कंपनियों को निवेशकों की वाहवाही मिलती है, वहीं जलेबीवाले को अब 'स्वास्थ्य जोखिम' बताया जा रहा है।

नेक इरादे, लेकिन ध्यान भटका : यह सही है कि मोटापा और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। भारत में उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोग तेजी से फैल रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है- छोटे स्ट्रीट वेंडर्स और स्थानीय खाद्य व्यवसायियों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, जबकि प्रोसेस्ड और ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर कोई रोक नहीं है? पैकेट वाले चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रोज़न स्नैक्स और मीठे 'हेल्दी बार्स' पर कोई अनिवार्य चेतावनी लेबल नहीं है—जबकि यही असली अपराधी हैं। दूसरी ओर, एक ताजा तला हुआ समोसा या गर्म जलेबी—जो आमतौर पर मजदूरों, छात्रों और दैनिक कामगारों द्वारा खाई जाती है—को अब 'संदिग्ध' माना जा रहा है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार नहीं, बल्कि 'नीतिगत अभिजात्य सोच' है, जो सुधार के नाम पर गरीबों को निशाना बना रही है।

सबसे पहले गरीबों पर असर : इसका सबसे अधिक असर उन लोगों पर पड़ेगा जो पहले से ही हाशिए पर हैं। शहरी गरीबों और ग्रामीण मजदूरों के लिए 5-10 का समोसा या 6 की जलेबी सिर्फ स्नैक नहीं, बल्कि एक अहम कैलोरी स्रोत है। रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाला 10 का

♦ ♦

मोटापा और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। भारत में उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोग तेजी से फैल रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है- छोटे स्ट्रीट वेंडर्स और स्थानीय खाद्य व्यवसायियों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, जबकि प्रोसेस्ड और ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर कोई रोक नहीं है? पैकेट वाले चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रोज़न स्नैक्स और मीठे 'हेल्दी बार्स' पर कोई अनिवार्य चेतावनी लेबल नहीं है—जबकि यही असली अपराधी हैं। दूसरी ओर, एक ताजा तला हुआ समोसा या गर्म जलेबी—जो आमतौर पर मजदूरों, छात्रों और दैनिक कामगारों द्वारा खाई जाती है—को अब 'संदिग्ध' माना जा रहा है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार नहीं, बल्कि 'नीतिगत अभिजात्य सोच' है, जो सुधार के नाम पर गरीबों को निशाना बना रही है।

सबसे पहले गरीबों पर असर : इसका सबसे अधिक असर उन लोगों पर पड़ेगा जो पहले से ही हाशिए पर हैं। शहरी गरीबों और ग्रामीण मजदूरों के लिए 5-10 का समोसा या 6 की जलेबी सिर्फ स्नैक नहीं, बल्कि एक अहम कैलोरी स्रोत है। रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाला 10 का वड़ा पाव या बोंडा उन स्थानों पर सस्ता पोषण देता है, जहां अन्य विकल्प नहीं हैं।

♦ ♦

वड़ा पाव या बोंडा उन स्थानों पर सस्ता पोषण देता है, जहां अन्य विकल्प नहीं हैं।

अगर इन पारंपरिक खाद्य पदार्थों को सांस्कृतिक रूप से कलंकित कर दिया गया और आर्थिक रूप से हतोत्साहित किया गया—बिना कोई सस्ता, पौष्टिक विकल्प दिए—तो लोग मजबूर होकर और भी सस्ते, लेकिन ज्यादा हानिकारक प्रोसेस्ड स्नैक्स की ओर मुड़ेंगे।

चेतावनी बोर्ड या आर्थिक पट्टी : मंत्रालय की यह योजना कई स्तरों पर असर कर सकती है- स्ट्रीट वेंडर्स के ग्राहकों की संख्या में कमी, सरकारी आयोजनों में मिठाइयों की मांग में गिरावट, और पारंपरिक खाद्य पदार्थों के प्रति सामाजिक शर्म की भावना। यह तरीका भारत की स्वास्थ्य समस्या का समाधान नहीं है।

आप आजमगढ़ के समोसे या तिरुचिरापल्ली के पकौड़े को विलेन बनाकर मोटापे को खत्म नहीं कर सकते। समाधान तभी संभव है जब बड़ी कंपनियों को जवाबदेह ठहराया जाए जो बाजार को अत्यधिक फैट, शुगर और एडिटिव्स से भरे स्नैक्स से पाट रही हैं—वह भी लगभग बिना किसी निगरानी के।

एक पाक-संस्कृति की सुरक्षा चादर : समोसे, लड्डू और जलेबी सिर्फ स्वाद नहीं हैं—वे भारत की पाक विरासत हैं, और साथ ही लाखों के लिए आजीविका का साधन भी। असंगठित खाद्य क्षेत्र करोड़ों को रोजगार देता है—जिनमें अधिकांश महिलाएं, जातिगत रूप से हाशिए पर रहने वाले, और भूमिहीन कामगार होते हैं, जिनके पास कोई औपचारिक नौकरी का साधन नहीं होता।

यह भारत की सबसे पुरानी और सबसे समावेशी स्वरोजगार योजना है—जिसमें न पूंजी चाहिए, न शिक्षा, न कॉर्पोरेट समर्थन। और अब इसे बिना किसी सलाह या मुआवज़े के खतरे में डाला जा रहा है।

एक चुपचाप होता बाजार कब्जा : यह मान लेना गलत होगा कि यह सिर्फ सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। भारत का पारंपरिक स्नैक बाजार, जो अब तक स्थानीय विक्रेताओं के हाथों में था, अब फूड कंपनियों के निशाने पर है। स्वाद या कीमत में मुकाबला न कर पाने के कारण वे स्वस्थ विकल्पों के नाम पर महंगे स्नैक्स बेचते हैं— 60 की फ्रोजन पफ पेस्ट्री, 40 की बेक्ड चिप्स, 35 की शुगर ओट बार्स—चमकदार पैकेजिंग और बैकग्राउंड में चल रहे लॉबिंग के साथ। और वहीं दूसरी ओर, ताजा तेल, गुड़ और बेसन से समोसा बनाने वाले हलवाई को चेतावनी बोर्ड से डराया जा रहा है, जबकि फैक्ट्री में बने स्नैक्स—जो प्रिज़रवेटिव्स से भरे होते हैं—को कोई पूछ नहीं रहा।

खतरनाक दोहरा मापदंड : भारत में अब भी प्रोसेस्ड फूड पर हाई फैट, हाई शुगर, हाई साल्ट कंटेंट के स्पष्ट चेतावनी लेबल अनिवार्य नहीं हैं। वहीं चिली, ब्राजील और मैक्सिको जैसे देश फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनियों को सख्ती से लागू करते हैं। लेकिन यहां अब भी यह मिथक कायम है- घर का बना खाना नुकसानदेह है, लैब में बना सुरक्षित है। यह नियामक असंतुलन परंपरा को दंडित करता है और औद्योगिक खाद्य दिग्गजों को इनाम देता है। नतीजा? एक सांस्कृतिक गिरावट, जहां क्षेत्रीय व्यंजन और सड़क किनारे का खानपान कॉरपोरेट स्नैक्स के लिए बलि चढ़ता है।

शर्मिंदा नहीं, सशक्त बनाएं : हां, भारत को अपनी स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना ही होगा। लेकिन मोटापे से लड़ने के लिए समोसे को बैन करना वैसा ही है, जैसे कोला की खपत घटाने के लिए लस्सी पर पाबंदी लगाना। समस्या खाने में नहीं, बल्कि नीति के अंधेपन में है। समोसे की दुकानों पर चेतावनी बोर्ड लगाने के बजाय हमें चाहिए एक समान नियम व्यवस्था। असली दोषियों—अत्यधिक प्रोसेस्ड और पैक्ड खाद्य पदार्थों—को निशाना बनाइए। उपभोक्ताओं को शिक्षित कीजिए। पोषण में निवेश कीजिए—परंपरा को रौंदे बिना। क्योंकि अगर भारत ने स्वास्थ्य के नाम पर अपनी स्ट्रीट फूड संस्कृति खो दी, तो हम सिर्फ कैलोरी नहीं गिनेंगे—बल्कि खोई नौकरियों, खोए स्वाद और खोई विरासत का भी हिसाब रखना पड़ेगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

नूर खान एयरबेस पर भारत की ऐतिहासिक स्ट्राइक से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे

मीडिया मैप न्यूज नेटवर्क

भारत की विनाशकारी स्ट्राइक पर नए खुलासे- नूर खान एयरबेस पूरी तरह तबाह! यह वैश्विक सैन्य पराक्रम का प्रतीक बन गया है! नई जानकारी सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर की गई स्ट्राइक ने कितनी जबरदस्त तबाही मचाई है। इसने भारत को वैश्विक सैन्य कौशल का नया पर्याय बना दिया है।

यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि विश्व स्तरीय सटीकता के साथ अंजाम दी गई ऐसी स्ट्राइक थी, जिसने पाकिस्तान की रणनीतिक रीढ़ तोड़ दी- उनकी वायु और परमाणु क्षमताएं एक झटके में खत्म कर दी गईं। जैसे-जैसे नई जानकारियां सामने आ रही हैं, पूरी दुनिया चौंक गई है। भारत ने आधुनिक युद्धकला की नई परिभाषा गढ़ दी है।

नूर खान एयरबेस- पाकिस्तान का अभेद्य किला : यह एयरबेस 3 से 5 मीटर मोटे स्टील-रेइनफोर्स्ड कंक्रीट के बंकरों से बना था, जो जमीन से 40-50 मीटर नीचे स्थित थे।

- अत्याधुनिक EMP (इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स) सुरक्षा, परमाणु-क्षम एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम, और फेरेडे केज जैसी तकनीकों से यह अति संरक्षित था।
- अमेरिकी कंपनी General Electric की मदद से बना यह आधारभूत ढांचा अमेरिका के सैटेलाइट संचार तंत्र से भी जुड़ा हुआ था।
- यह पाकिस्तान का अंतिम CyI (Command, Control, Communications, Computers & Intelligence) केंद्र था- एक ऐसा बंकर जो परमाणु हमले के बाद भी काम करता। इसका स्थान रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर (GHQ) से महज चार किमी दूर है, एक गुप्त, सुरक्षित मार्ग से जुड़ा हुआ।

भारतीय स्ट्राइक - परिशुद्धता की पराकाष्ठा : दो वर्षों की विस्तृत योजना और अभ्यास के बाद भारतीय वायुसेना ने इस पर हमला किया। टारगेट था एक मात्र 2×2 फुट का वेंटिलेशन शाफ्ट— जो 600 किमी दूर से लगभग सुपरसोनिक गति पर निशाना बनाया गया।

- यह सटीकता भारत की स्वदेशी NavIC सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम द्वारा संभव हुई।
- इस हमले में दो मोबाइल कमांड ट्रक, एक Level C सुरक्षित बंकर (केवल टॉप-लेवल अधिकारियों के लिए), और संभवत: Ra'ad क्रूज़ मिसाइल भंडारण नष्ट कर दिया गया।
- सैटेलाइट इमेज से पुष्टि हुई कि 40×40 मीटर का क्षेत्रफल पूरी तरह चपटा हो गया, और वहां तापमान सामान्य से 2.6ए C से 4.1ए C अधिक पाया गया।

वैश्विक प्रभाव-पूरी दुनिया स्तब्ध : इस हमले ने पाकिस्तान के अमेरिकी SATCOM लिंक को काट दिया, जिससे उनके F-16, AWACS और ISR सिस्टम अंधे हो गए।

- EU Copernicus और US Global Hawk की थर्मल इमेजिंग से पुष्टि हुई कि क्रायोजेनिक हथियार भंडारण और डाटा सेंटर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं।
- यह केवल फिजिकल स्ट्राइक नहीं थी- यह एक साइबर-काइनेटिक हमला था जिसने पाकिस्तान के साइबर कमांड को भी ऑफलाइन कर दिया।
- स्ट्राइक से पहले का इंटरनेट ब्लैकआउट दिखाता है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक पूर्व-नियोजित साइबर हमला भी किया था।

भारत का संदेश- "Decapitation Lite" **युद्ध की नई परिभाषा** : यह अभियान पूरी तरह नष्ट करने के बजाय रणनीतिक

अपंगता लाने पर केंद्रित था।

- भारत ने सिर्फ बंकर नहीं उड़ाया-उसने पाकिस्तान की सामरिक आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया।
- वेंटिलेशन शाफ्ट को लक्ष्य बनाकर भारत ने न्यूनतम कोलैटरल डैमेज के साथ अधिकतम असर डाला।
- NavIC सिस्टम ने 600 किमी दूर से एक छोटे से लक्ष्य पर मिसाइल को निर्देशित कर यह दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ आकाश को नहीं, युद्ध की दिशा को भी नियंत्रित करता है।

ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) **और** HUMINT **की भूमिका** : दो वर्षों तक लगातार मॉक स्ट्राइक्स, OSINT, और शायद HUMINT (मानव इंटेलिजेंस) द्वारा जानकारी इकट्ठा की गई।

- Falcon Striker 72 कोडनेम वाले स्रोत की रहस्यमय गुमशुदगी से यह संकेत मिलता है कि भारत को बेहद सटीक अंदरूनी जानकारी थी।

वैश्विक प्रतिक्रियाएँ और पाकिस्तान की चुप्पी : NATO- ग्रेड बंकर की कमजोरी उजागर हुई, जिससे अब अन्य देश अपने सिस्टम की समीक्षा करने को मजबूर हैं।

- भारत ने यह दिखा दिया कि वह दुश्मन के Nuclear Command Center को भी निष्क्रिय कर सकता है- कहीं भी, कभी भी।
- पाकिस्तान यह मान भी नहीं सकता कि उनका अत्यंत सुरक्षित बंकर नष्ट हो गया है- यह एक रणनीतिक हार है जिसकी न तो वह पुष्टि कर सकता है और न ही प्रतिशोध ले सकता है।

ग्यारह साल बाद : मोदी का भारत आकांक्षाओं और आंदोलनों के बीच

ग्यारह साल पहले, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालते हुए परिवर्तनकारी बदलाव का वादा किया था। उनके सत्ता में आने से पूरे देश में—कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल तक—आशा की लहर दौड़ गई थी। बहुतों ने इसे एक नए युग की शुरुआत माना।

उनकी शुरुआती और सबसे प्रतीकात्मक पहलों में से एक, स्वच्छ भारत अभियान, ने राष्ट्रीय चेतना को झकझोर दिया। मोदी के स्वच्छता के आह्वान पर भारतीयों ने झाड़ू उठाई और सफाई में जुट गए। जबकि पिछली यूपीए सरकार ने 2012 में एक सीमित 'क्लीन इंडिया' अभियान शुरू किया था, वह कभी जन-आंदोलन नहीं बन पाया। इसके विपरीत, स्वच्छ भारत ने सड़कों, कचरे के ढेरों और शहरों की तस्वीर बदलनी शुरू की। एक समय ऐसा लगा कि हर मोहल्ला सिविल लाइन्स की तरह साफ और व्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन नगर पालिका स्तर पर इस ऊर्जा को बनाए रखना

प्रो. शिवाजी सरकार

चुनौतीपूर्ण साबित हुआ।

2014 के चुनाव में महंगाई देन जैसा तीखा नारा गूंजा—उस समय मुद्रास्फीति 12.17% पर थी। कीमतों में गिरावट उपभोक्ताओं और उद्योग जगत दोनों की साझा आकांक्षा थी। समय के साथ शीर्ष स्तर की मुद्रास्फीति भले कम हुई हो, लेकिन आम लोग अंडे, मछली, कपड़ा और फल जैसी ज़रूरतों की लगातार बढ़ती कीमतों से जूझते रहे।

कश्मीर में दशकों पुराने अशांति के समाधान की उम्मीद जगी थी। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A का हटाया जाना एक साहसिक कदम था, जिसने क्षेत्र की विशेष संवैधानिक स्थिति को समाप्त किया। लेकिन पहलगाम के पास हुए हालिया हमलों जैसे हिंसक घटनाएं बताती हैं कि जड़ें अभी भी उखड़ी नहीं हैं। लद्दाख और अरुणाचल में भी चीन के साथ तनाव बढ़ा है, जहां घुसपैठ की घटनाएं सुरक्षा विमर्श को प्रभावित कर रही हैं। डोगरा काल की सीमाएं एक बार फिर परीक्षण में हैं।

उपमहाद्वीप में अधिक एकता की आशाएं थीं। आकांक्षी भारत को पड़ोसी देशों के लिए आर्थिक आधार स्तंभ के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन सार्क का लगभग विघटन, बांग्लादेश और मालदीव के साथ तनावपूर्ण संबंध, और क्षेत्रीय असहजता एक अलग ही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। घरेलू मोर्चे पर भी कई अप्रत्याशित घटनाएं हुईं। मणिपुर में मेइती समुदाय से जुड़े आरक्षण विवाद से उपजे जातीय संघर्ष ने राज्य को झुलसा दिया है। वहीं, विकास के प्रतीक बुलडोजर अब सरकारी शक्ति के विवादास्पद प्रतीक बन चुके हैं।

2016 की नोटबंदी ने समानांतर (काले) अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया, लेकिन इसके कई अप्रत्याशित दुष्प्रभाव भी हुए। रेहड़ी-पटरी वाले, छोटे व्यापारी और अनौपचारिक क्षेत्र के व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुए। सरकार ने कहा कि

इससे भ्रष्टाचार और काले धन पर लगाम लगेगी, लेकिन 17.74 लाख करोड़ की पूरी रकम अंततः बैंकों में वापस आ गई। इस बीच, डिजिटल युग में भी चलन में मुद्रा का आकार बढ़कर मई 2025 में 38.35 लाख करोड़ हो गया है, जो 2022 से सालाना 7.2% की दर से बढ़ रहा है। खाद्य मुद्रास्फीति, जो 2018-20 में 6.7% और 2020-21 में 9.1% तक पहुंची थी, मई 2025 में गिरकर 2.85% पर आ गई है, लेकिन यह अब भी हर घर की चिंता बनी हुई है। पूरे दशक (2015-2024) की औसत मुद्रास्फीति लगभग 5.86% रही है। कुछ क्षेत्रों में कंपनियों के मुनाफे रिकॉर्ड 27% तक बढ़े हैं, मुख्यतः रणनीतिक कीमत बढ़ोतरी के कारण, हालांकि औद्योगिक विकास और विनिर्माण निवेश अपेक्षाकृत धीमे रहे हैं।

रोजगार का मुद्दा अब भी एक नासूर बना हुआ है। 'नए भारत' की कथा के बावजूद, नौकरियों की रचना जनसंख्या की ज़रूरतों के अनुसार नहीं हो सकी। इसी बीच, जनवरी 2024 से शेयर बाजार दबाव में है, जब एक प्रमुख भारतीय समूह पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई। अक्टूबर 2024 से बाजार पूंजीकरण करीब .1 ट्रिलियन गिरा है, जबकि इसी दौरान चीन की बाज़ार पूंजी .2 ट्रिलियन बढ़ गई। विदेशी निवेशक अल्पकालिक निवेश करते रहे हैं, लेकिन दीर्घकालिक विश्वास में कमी आई है। बीएसई और निफ्टी जैसी सूचकांकों की अस्थायी बढ़तें मूलभूत ढांचे की समस्याओं को नहीं छुपा सकतीं।

फिर भी, हर बात नकारात्मक नहीं रही है। भारत के अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों ने सराहनीय प्रगति की है। इसरो ने उपग्रहों के झुंड लांच किए हैं और टेलीकॉम आधुनिकीकरण में कदम बढ़ाए हैं। हालांकि, एलन मस्क की Starlink जैसी विदेशी तकनीकी कंपनियों के प्रवेश से कीमतों और इंटरनेट पहुंच को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। कुछ अपेक्षित नीतिगत बदलाव—जैसे कुछ कांग्रेस युग की नीतियों को पलटना—अब तक नहीं हुए हैं। उदाहरण के लिए 10 साल पुराने वाहनों पर प्रतिबंध अब भी लागू है, जबकि 40 साल पुराने विमान आज भी सेवा में हैं।

सामाजिक स्तर पर, खान-पान, पहनावे, भाषा और असहमति को लेकर वर्जनाओं की संस्कृति और गहराई है। असहमति जताना अब अधिक जोखिमपूर्ण प्रतीत होता है। राजनीतिक भाषण में अपमानजनक भाषा सामान्य हो चुकी है, और संसद की गरिमा प्रभावित हुई है। एक ही सत्र में 140 से अधिक विपक्षी सांसदों (जिसमें राहुल गांधी भी शामिल थे) का निष्कासन कई लोगों को स्तब्ध कर गया। विपक्ष के भाषणों को अकसर विलोपित कर दिया जाता है, और लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका पर प्रश्न उठे हैं।

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठे हैं, विशेषकर हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के नतीजों को लेकर न्यायिक चुनौतियां जारी हैं। राजनीति का सांप्रदायीकरण—घृणास्पद भाषणों, लक्षित विध्वंस और असहमति जताने वालों की गिरफ्तारी के रूप में—सामाजिक ताने-बाने को कमजोर कर रहा है। सरकार का दावा है कि उसने अभूतपूर्व प्रगति की है, लेकिन यह प्रगति विवादों में घिरी हुई है।

इन सबके बीच एक विरोधाभास स्पष्ट है- भारत ने पिछले ग्यारह वर्षों में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन गंभीर ठोकरें भी खाईं हैं। मोदी के नेतृत्व में देश ने निश्चित रूप से भौगोलिक और राजनीतिक रूप से कायापलट देखा है। फिर भी, कई वादे अधूरे हैं। एक समावेशी, आर्थिक रूप से सशक्त और सामाजिक रूप से सामंजस्यपूर्ण भारत का सपना अब भी लोगों के दिलों में जीवित है, लेकिन आगे की राह संतुलन, संवाद और चुनावी जीत से आगे जाकर लोकतांत्रिक मूल्यों की सच्ची निष्ठा की मांग करती है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया शिक्षक है)

♦♦

रोजगार का मुद्दा अब भी एक नासूर बना हुआ है। 'नए भारत' की कथा के बावजूद, नौकरियों की रचना जनसंख्या की ज़रूरतों के अनुसार नहीं हो सकी। इसी बीच, जनवरी 2024 से शेयर बाजार दबाव में है, जब एक प्रमुख भारतीय समूह पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई। अक्टूबर 2024 से बाजार पूंजीकरण करीब .1 ट्रिलियन गिरा है, जबकि इसी दौरान चीन की बाज़ार पूंजी .2 ट्रिलियन बढ़ गई। विदेशी निवेशक अल्पकालिक निवेश करते रहे हैं, लेकिन दीर्घकालिक विश्वास में कमी आई है। बीएसई और निफ्टी जैसी सूचकांकों की अस्थायी बढ़तें मूलभूत ढांचे की समस्याओं को नहीं छुपा सकतीं। फिर भी, हर बात नकारात्मक नहीं रही है। भारत के अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों ने सराहनीय प्रगति की है। इसरो ने उपग्रहों के झुंड लांच किए हैं और टेलीकॉम आधुनिकीकरण में कदम बढ़ाए हैं। हालांकि, एलन मस्क की स्ह्लड्ढद्यद्बठ्ठद्म जैसी विदेशी तकनीकी कंपनियों के प्रवेश से कीमतों और इंटरनेट पहुंच को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। कुछ अपेक्षित नीतिगत बदलाव—जैसे कुछ कांग्रेस युग की नीतियों को पलटना—अब तक नहीं हुए हैं। उदाहरण के लिए 10 साल पुराने वाहनों पर प्रतिबंध अब भी लागू है, जबकि 40 साल पुराने विमान आज भी सेवा में हैं।

♦♦

एयर इंडिया फ्लाइट 182 की याद में : कनाडा पर सबसे घातक आतंकी हमले को 40 वर्ष

प्रभजोत सिंह

एयर इंडिया फ्लाइट 182 की भयावह बमबारी की त्रासदी के चालीस साल बाद, पीड़ितों के परिवार और मित्र कनाडा, आयरलैंड और भारत में एकत्र हुए, ताकि 329 जानों की याद में श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके— यह हमला कनाडा के इतिहास में अब तक का सबसे घातक आतंकवादी हमला है। 23 जून 1985 को, एयर इंडिया फ्लाइट AI 182, जो मॉन्ट्रियल से दिल्ली जा रही थी (लंदन के रास्ते), को 31,000 फीट की ऊंचाई पर आयरिश हवाई क्षेत्र में एक बम से गिरा दिया गया। विमान आयरलैंड के काउंटी कॉर्क के तट के पास अटलांटिक महासागर में गिर गया। पीड़ितों में 268 कनाडाई नागरिक शामिल थे। जापान के नारिता हवाई अड्डे पर एक संबंधित बम विस्फोट में दो और लोग मारे गए थे।

अंतरराष्ट्रीय श्रद्धांजलियां : आयरलैंड के काउंटी कॉर्क के आहाकिस्टा गांव में-जो दुर्घटनास्थल के सबसे निकट है-बचे हुए लोग, स्थानीय निवासी और अंतरराष्ट्रीय मेहमान 1986 में बनाए गए समुद्र किनारे के स्मारक पर एकत्र हुए। इस गांव का पीड़ितों के परिवारों के लिए विशेष महत्व है। त्रासदी के बाद के दिनों में, स्थानीय निवासियों ने दुनिया भर से आए शोक संतप्त परिवारों को अपने घरों में आश्रय और सहारा दिया था। कनाडा में, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस अवसर पर और आतंकवाद के पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय स्मृति दिवस पर एक भावुक बयान जारी किया।

'यह आतंकवादी हमला हमारे देश के इतिहास में अब तक का सबसे घातक रहा है—एक ऐसा हादसा जिसे हम कभी नहीं भूल सकते,' कार्नी ने कहा। 'हम उन परिवारों और मित्रों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और आतंकवाद व हिंसक उग्रवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं—चाहे वह देश में हो या विदेश में।' उन्होंने यह भी बताया कि कनाडा की नई सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने के लिए धन में वृद्धि कर रही है। 'कनाडा की सरकार आतंकवाद के पूरी तरह खिलाफ खड़ी है,' उन्होंने कहा।

नई दिल्ली में स्मृति कार्यक्रम : नई दिल्ली में कनाडा हाउस में एक स्मृति कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कनाडा की कार्यवाहक उच्चायुक्त जेनिफर डॉबेनी, आयरलैंड के राजदूत केविन केली, भारतीय सरकारी अधिकारी, राजनयिक और पीड़ितों के परिवारों सहित एयर इंडिया के पूर्व चालक दल के सदस्य शामिल हुए। 'यह बरसी हमें आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने और वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए कार्य करने की आवश्यकता की याद दिलाती है,' डॉबेनी ने समारोह के दौरान कहा। 'आज, हम हर उस अनमोल जीवन को याद करते हैं जो हमने खोया और पीड़ितों और उनके परिवारों के समर्थन की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।'

राजदूत केली ने बमबारी के बाद दिखाए गए सहयोग की भावना को याद किया। 'हालांकि चार दशक बीत चुके हैं, लेकिन दर्द अब भी ताजा है। और उसी तरह आहाकिस्टा के लोगों की करुणा भी, जिन्होंने शोकग्रस्त परिवारों को अपनाया। आज, हम आयरलैंड, भारत और कनाडा में एकजुट हैं-स्मरण और संकल्प के साथ।'

श्रद्धांजलि के प्रतीक कार्य : नई दिल्ली के समारोह में एक पेड़ लगाया गया, ताकि पीड़ितों की याद को जीवित रखा जा सके, और एक मिनट का मौन रखा गया। उपस्थित लोगों ने एक श्रद्धांजलि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए और हाल ही में अहमदाबाद में हुए एक विमान हादसे के पीड़ितों को भी श्रद्धांजलि दी गई। फ्लाइट 182 की बमबारी ने कनाडा की आतंकवाद के प्रति संवेदनशीलता को उजागर किया और इसके राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर गहरा प्रभाव डाला। प्रारंभिक जांच और अभियोजन की विफलताओं के बावजूद, इस त्रासदी ने विमानन सुरक्षा और खुफिया समन्वय में सुधारों की नींव रखी।

आज भी कई परिवार न्याय और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस गहरे दु:ख के बीच, हर साल होने वाले ये स्मृति कार्यक्रम सामूहिक स्मृति, सहनशीलता और शांति की स्थायी पुकार के शक्तिशाली प्रतीक बने हुए हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

भारतीय सिनेमा में वेब सीरीज का बढ़ता प्रभाव

मीडिया मैप न्यूज नेटवर्क

भारतीय सिनेमा और वेब सीरीज का इतिहास काफी पुराना है और इसमें कई उतार-चढ़ाव देखे गए हैं। भारतीय सिनेमा ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है और वेब सीरीज के आगमन ने इसे और भी विविध और रोचक बना दिया है।

भारतीय सिनेमा का इतिहास : भारतीय सिनेमा का इतिहास १९१३ से शुरू होता है, जब दादा साहब फाल्के ने पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। इसके बाद, भारतीय सिनेमा ने कई उतार-चढ़ाव देखे और विभिन्न शैलियों और विषयों पर फिल्में बनाई गई।

हिंदी सिनेमा : हिंदी सिनेमा भारतीय सिनेमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें कई प्रसिद्ध अभिनेता और अभिनेत्री हुए हैं। हिंदी सिनेमा ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है और इसमें कई सफल फिल्में बनाई गई हैं।

वेब सीरीज का आगमन : वेब सीरीज का आगमन भारतीय मनोरंजन उद्योग में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। वेब सीरीज ने भारतीय दर्शकों को नए और अनोखे विषयों पर कहानियां देखने का अवसर प्रदान किया है।

वेब सीरीज की विशेषताएं : वेब सीरीज की कई विशेषताएं हैं जो इसे पारंपरिक टेलीविजन शो से अलग बनाती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं-

- **नई और अनोखी कहानियां :** वेब सीरीज में नई और अनोखी कहानियां दिखाई जाती हैं जो पारंपरिक टेलीविजन शो से अलग होती हैं।
- **अधिक स्वतंत्रता :** वेब सीरीज के निर्माताओं को अधिक स्वतंत्रता होती है जिससे वे अपने विचारों और कहानियों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं।
- **बेहतर गुणवत्ता :** वेब सीरीज की गुणवत्ता पारंपरिक टेलीविजन शो से बेहतर होती है और इसमें अधिक विस्तृत कहानियां और बेहतर अभिनय होता है।

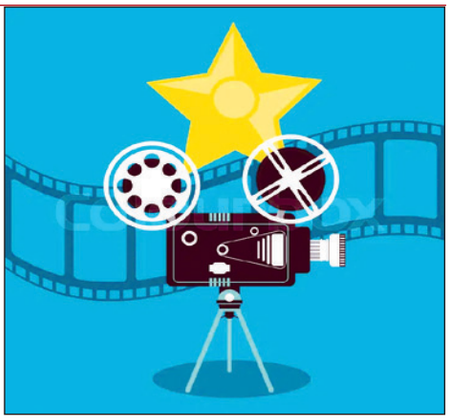

भारतीय वेब सीरीज की सफलता : भारतीय वेब सीरीज ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है और इसमें कई सफल सीरीज बनाई गई हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सीरीज हैं-

- **सैक्रेड गेम्स :** यह एक अपराध थ्रिलर सीरीज है जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर आधारित है।
- **मिर्जापुर :** यह एक अपराध ड्रामा सीरीज है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले पर आधारित है।
- **पाताल लोक :** यह एक अपराध थ्रिलर सीरीज है जो दिल्ली के पुलिस अधिकारी के जीवन पर आधारित है।

भारतीय सिनेमा और वेब सीरीज ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है और इसमें कई सफल फिल्में और सीरीज बनाई गई हैं। वेब सीरीज का आगमन भारतीय मनोरंजन उद्योग में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है और इसमें नई और अनोखी कहानियां दिखाई जाती हैं। भारतीय सिनेमा और वेब सीरीज का भविष्य उज्ज्वल है और इसमें और भी अधिक सफल फिल्में और सीरीज बनाई जाएंगी।

नेहरू जी की इतनी कटु आलोचना क्यों

संघ परिवार द्वारा प्रस्तुत ऊंची जाति की हिंदू राजनीति और उनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू के प्रति बरती जा रही स्थायी शत्रुता भारतीय राजनीति का एक विचित्र विरोधाभास है। नेहरू एक कश्मीरी ब्राह्मण थे—एक ऐसा समुदाय जो स्वयं को वैदिक आर्यों की सबसे शुद्ध वंशावली मानता है—और वे एक कुलीन वर्ग से थे, जिस वर्ग की आज आरएसएस-भाजपा रक्षा करने का दावा करती है। फिर भी, नेहरू ही उनके राजनीतिक आख्यानों में सबसे ज्यादा निशाने पर हैं।

पहली पीढ़ियों द्वारा 'पंडितजी' के रूप में श्रद्धा से पुकारे जाने वाले नेहरू प्रगतिशील विचारों और समाजवादी सोच वाले व्यक्ति थे। वे सामाजिक सुधारक तो नहीं थे, लेकिन जातिवादी भी नहीं थे। उन्होंने पारंपरिक सामाजिक ढांचे को तोड़ने की कोशिश नहीं की, पर उसे खुले रूप से समर्थन भी नहीं दिया। विडंबना यह है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, नेहरू के बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने उनकी मृत्यु पर एक अत्यंत भावुक श्रद्धांजलि दी थी।

ऐसे इतिहास को देखते हुए आज भाजपा-आरएसएस नेताओं द्वारा नेहरू के खिलाफ चलाया जा रहा नफरत का अभियान समझ से परे है—खासकर तब जब नेहरू दशकों से राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक हो चुके हैं। और भी अजीब बात यह है कि उनके आज के सबसे मुखर आलोचक तो उनके निधन (1964) के काफी बाद पैदा हुए हैं और स्वतंत्रता संग्राम व राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को शायद ही समझते हैं।

नेहरू के कार्यकाल की आलोचना पहले भी हुई थी, विशेषकर 1962 के चीन युद्ध के बाद, जिसने उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन तब भी उनके सबसे तीव्र आलोचक उनके देशभक्त होने या उनके दृष्टिकोण पर सवाल नहीं उठाते थे। आज के हमले अलग हैं—व्यक्तिगत, विषैले, और अक्सर ऐतिहासिक समझ से रहित।

नेहरू के विकास मॉडल को अक्सर औद्योगीकरण पर अधिक जोर देने के लिए दोषी ठहराया गया। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की उनकी कल्पना ने वह बुनियादी ढांचा खड़ा किया जिससे हम आज लाभ उठा रहे हैं। बांध, वैज्ञानिक संस्थान, और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां—ये सब भारत को आधुनिक बनाने की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा थीं। उस समय के आलोचक, जैसे लोहिया स्कूल के समाजवादी, उन्हें अभिजात्यवादी मानते थे— 'भारत' के बजाय 'इंडिया' का प्रतिनिधि। लेकिन उस समय की आलोचना, आज की तरह व्यक्तिगत या ऐतिहासिक विकृति पर आधारित नहीं थी।

तो फिर आज इतना क्रोध क्यों? नेहरू आज इतना तीव्र भावनात्मक प्रतिरोध क्यों पैदा करते हैं?

गहराई से देखने पर पता चलता है कि आज नेहरू की आलोचना उस समाज के एक

'पंडितजी' के रूप में श्रद्धा से पुकारे जाने वाले नेहरू प्रगतिशील विचारों और समाजवादी सोच वाले व्यक्ति थे। वे सामाजिक सुधारक तो नहीं थे, लेकिन जातिवादी भी नहीं थे। उन्होंने पारंपरिक सामाजिक ढांचे को तोड़ने की कोशिश नहीं की, पर उसे खुले रूप से समर्थन भी नहीं दिया। विडंबना यह है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, नेहरू के बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने उनकी मृत्यु पर एक अत्यंत भावुक श्रद्धांजलि दी थी। ऐसे इतिहास को देखते हुए आज भाजपा-आरएसएस नेताओं द्वारा नेहरू के खिलाफ चलाया जा रहा नफरत का अभियान समझ से परे है–खासकर तब जब नेहरू दशकों से राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक हो चुके हैं। और भी अजीब बात यह है कि उनके आज के सबसे मुखर आलोचक तो उनके निधन (1964) के काफी बाद पैदा हुए हैं और स्वतंत्रता संग्राम व राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को शायद ही समझते हैं। नेहरू के कार्यकाल की आलोचना पहले भी हुई थी, विशेषकर 1962 के चीन युद्ध के बाद, जिसने उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन तब भी उनके सबसे तीव्र आलोचक उनके देशभक्त होने या उनके दृष्टिकोण पर सवाल नहीं उठाते थे। आज के हमले अलग हैं–व्यक्तिगत, विषैले, और अक्सर ऐतिहासिक समझ से रहित।

वर्ग को अपील करती है जो उदारीकरण के बाद उभरा है—खुदरा, रियल एस्टेट, बैंकिंग, बीपीओ और छोटे व्यवसायों में काम करने वाले पेशेवर, जो दबावपूर्ण और लाभ-केंद्रित माहौल में काम करते हैं। उनका इतिहास ज्ञान अक्सर सतही होता है, लेकिन वे आत्मविश्वास से आलोचना करते हैं। उनके लिए सफलता का पैमाना भौतिक संपन्नता है, और उनके दृष्टिकोण में नेहरू का संस्थागत अनुशासन, नियमन और सामाजिक न्याय पर बल अप्रासंगिक लगता है।

इन भावनाओं को अकादमिक जगत, मीडिया और आकांक्षी मध्य वर्ग के छद्म-बौद्धिक लोग और भी हवा देते हैं। उनके लिए वर्तमान शासन या असमानता की जटिलताओं से जूझना कठिन है, इसलिए किसी ऐतिहासिक व्यक्ति पर हमला करना आसान विकल्प बन जाता है। संघ परिवार की विचारधारा से जुड़े अन्य लोग इस विरोध में सांप्रदायिक नजरिया भी लाते हैं, जिससे नेहरू एक सुविधाजनक वैचारिक बलि का बकरा बन जाते हैं।

नेहरू का दर्शन उस भारत के मूल्यों के विपरीत खड़ा होता है, जो आज बाजार-प्रधान बन चुका है। वे मानते थे कि राज्य को व्यापार पर नियंत्रण रखना चाहिए, कमजोरों की रक्षा करनी चाहिए और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करनी चाहिए। उनके अनुसार, आर्थिक प्रगति संस्थागत ईमानदारी या सामाजिक जिम्मेदारी की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। जबकि उनके आलोचक बेलगाम पूंजीवाद की प्रशंसा करते हैं और गरीबों या हाशिये के लोगों पर इसके प्रभाव को नजरअंदाज कर देते हैं।

इसीलिए नेहरू उनके लिए आंख की किरकिरी बने हुए हैं। वे एक नैतिक प्रतिबंध का प्रतीक हैं—यह याद दिलाते हैं कि राष्ट्र निर्माण सिर्फ जीडीपी या शेयर बाजार के आंकड़ों से नहीं होता। उनका उत्तराधिकार उन लोगों के लिए असहज है जो एक ऐसे तंत्र में फलते-फूलते हैं जहां शॉर्टकट, पूंजीपति-साठगांठ और मुनाफाखोरी सामान्य हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, नेहरू आधुनिक, आदर्शवादी भारतीयों के प्रतीक थे—नौकरशाहों, न्यायाधीशों, शिक्षकों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए जो ईमानदारी, समानता और तर्कसंगत शासन के मूल्यों में विश्वास रखते थे। इन लोगों को आज कॉरपोरेट और राजनीतिक शक्तियों ने हाशिये पर धकेल दिया है, लेकिन फिर भी वे भारत के संसाधनों और लोगों के अंधाधुंध शोषण के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। नेहरू को बदनाम करना इस प्रतिरोध को कमजोर करना है—लालच और निरंकुश सत्ता पर लगी आखिरी नैतिक रोक को हटाना।

विडंबना यह है कि वही वर्ग जिसने नेहरू द्वारा बनाए गए बुनियादी ढांचे से सबसे ज्यादा लाभ उठाया है, अब उन्हें ही अवमानित करने पर तुला है। वे सड़कें, उद्योग और संस्थान जिनसे आज वे मुनाफा कमा रहे हैं, उसी व्यक्ति की देन हैं जिसे वे दोषी ठहराते हैं। लेकिन उपभोक्तावादी मानसिकता और ऐतिहासिक समझ की कमी के चलते वे नेहरू को भारत की हर समस्या—ब्यूरोक्रेसी से लेकर गरीबी तक—का दोषी ठहराते हैं, बिना यह समझे कि आज़ादी के बाद देश ने कितनी चुनौतियां झेली थीं।

असल में, यह नेहरू-विरोधी अभियान इतिहास के प्रति जवाबदेही नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत को मिटाने का प्रयास है जो बाजार के निरंकुश वर्चस्व के रास्ते में खड़ी है। नेहरू के खिलाफ लगाए गए आरोप ज्यादातर निराधार हैं और असल एजेंडे से ध्यान भटकाने के लिए गढ़े गए हैं—आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को केंद्रीकृत करने के लिए, उन संस्थाओं और मूल्यों को कमजोर करके जिनकी उन्होंने नींव रखी थी।

आखिर में, नेहरू उस भारत की कल्पना करते थे जो समावेशी, दूरदर्शी और लोकतांत्रिक आदर्शों में विश्वास रखता हो। उनके युग या योगदान को समझे बिना की गई आलोचना हमारे लोकतंत्र को मजबूत नहीं करती—बल्कि उसे कमजोर कर देती है। यदि हम अपने अतीत के सबक भूल जाते हैं, तो हमें वही गलतियां दोहरानी पड़ेंगी।

मीडिया मैप न्यूज नेटवर्क

मीडिया मैप

में विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें

One full Color Page : Rs. 150,000/- (one lakh fifty thousand only)
One full Page (Black and white) : Rs. 100000/- (One lakh only)

69 ज्ञानखंड-4 इंदिरापुरम, गाजियाबाद- 201014 (उत्तर प्रदेश)
दूरभाष : 9810385757/9910069262

Email : editor@mediamap.co.in

क्या किशोरों के लिए POCSO कानून को शिथिल करना एक विकल्प है

अमिताभ श्रीवास्तव

क्या कठोर POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) को उस समय स्थगित किया जाना चाहिए जब पीड़िता स्वयं इसे हटाने की मांग कर रही हो? पिछले सप्ताह भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा निर्णय दिया जिसने देशभर में बच्चों और यौन अपराधों से संबंधित कानूनी और सामाजिक संगठनों के बीच बहस छेड़ दी है। यह मामला पश्चिम बंगाल का है, जहां 2018 में 13/14 साल की एक लड़की ने अपना घर छोड़ दिया और एक 25 वर्षीय युवक के साथ रहने लगी। लड़की की मां जब उस युवक के घर अपनी बेटी को वापस लाने पहुंचीं, तो लड़की ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। मां की शिकायत पर युवक के खिलाफ POCSO की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, जो 2023 में बनाया गया कानून है।

इसी बीच लड़की ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन लड़की की मां ने न तो उसे और न ही अपनी नवासी को स्वीकार किया और उनसे मिलने भी नहीं गईं। इस लंबे केस में जो कई कोर्ट और पुलिस स्टेशनों से होकर गुज़रा, अंततः युवक को गंभीर धाराओं में दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुना दी गई। वहीं दूसरी ओर, लड़की न केवल अपनी बेटी की देखभाल कर रही है, बल्कि अपने पति की रिहाई के लिए भी लड़ाई लड़ रही है। यानी पीड़िता की उस व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, जिसने और जिसकी परिवार ने उसकी बच्ची की देखरेख की, जबकि उसका जैविक परिवार उसे पूरी तरह छोड़ चुका है।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं लिज़ मैथ्यू और माधव दीवान को अमिकस क्यूरी नियुक्त किया, ताकि वे कोर्ट को निर्णय लेने में मदद कर सकें। इन दोनों अधिवक्ताओं ने अध्ययन के बाद सुझाव दिया कि इस मामले को सहमति से बने संबंध के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें किशोर शामिल हैं जिनकी जैविक ज़रूरतें और हार्मोन उन्हें शारीरिक गतिविधियों की ओर प्रेरित करते हैं, जो व्यस्क अपराध व्यवस्था में आपराधिक मानी जाती हैं। उन्होंने देश में ऐसे कई फैसलों का हवाला दिया जहाँ किशोरों के मामलों में कोर्ट ने नरम दृष्टिकोण अपनाया है।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि स्कूली पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए ताकि बच्चे अपने कार्यों, भावनाओं और परिणामों के बारे में जागरूक हो सकें और जब वे 'लक्ष्मण रेखा' पार करें तो उन्हें इसका मतलब पता हो। इन सुझावों का समर्थन करते हुए न्यायमूर्तियों ने भी कहा कि बच्चों को उनके शरीर और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करने के लिए यौन शिक्षा स्कूलों में शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव से एक विशेषज्ञ समिति गठित कर 25 जुलाई तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

MediaMap से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर ने इस निर्णय की कड़ी आलोचना की। 'कोर्ट किसी नाबालिग के मामले में सहमति से संबंध की बात कैसे कर सकता है? क्या उन्हें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों की जानकारी नहीं है? अगर यह रुख स्वीकार किया गया तो देश में किशोरों से जुड़े अपराधों का सैलाब आ जाएगा।' डॉ. किरण अग्रवाल, जो एक बाल रोग विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ने कहा, 'यह पहली बार नहीं है जब स्कूलों में यौन शिक्षा देने की बात की जा रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस काम में शामिल रही हूं, लेकिन सरकार और स्कूल दोनों ही बच्चों को यौन शिक्षा देने की बात पर विरोध करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें सेक्स एक्ट सिखा रहे हैं, जिसकी जानकारी उन्हें पहले से ही इंटरनेट और मोबाइल के जरिए है। यौन शिक्षा का मतलब है शरीर और स्वास्थ्य से जुड़ी बुनियादी जानकारी देना। लेकिन %यौन% शब्द सुनते ही वे बिदक जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार इसे कैसे संभालेगी, यह देखना होगा।'

डॉ. संगीता सक्सेना, Enfold Proactive Health Trust नामक NGO की सह-संस्थापक, जो सिडनी से बोल रही थीं, कहती हैं, 'Enfold 2001 से यौनता और व्यक्तित्व पर काम कर रहा है। हममें से कई जानते हैं कि POCSO कानून को कई बार माता-पिता अपने बच्चों को सज़ा देने के हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं जब वे उनकी बात नहीं मानते। वहीं अधिकांश माता-पिता अपने बच्चों को यौन शिक्षा नहीं देते और न ही स्कूलों को ऐसा करने देना चाहते हैं।'

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

जीवन के सभी मुद्दों का स्थाई समाधान है 'भगवत गीता'

भगवत गीता यह वह 'पवित्र गीत' है, जिसे भगवान श्रीकृष्ण जी ने स्वयं अपने श्री मुख से गाया है, अर्थात वह गीत जिसे भगवान ने स्वयं गाया है इसीलिए मूल रूप से यह 'भगवत गीत' है जो अंग्रजी में 'भागवत गीता' हो गया जैसे 'योग' अंग्रेजी में 'योगा' हो गया 'वेद' अंग्रेजी में 'वेदा' हो गया ,यह सभी को जानना बहुत जरुरी है कि इसे भगवान ने स्वयं अपने श्री मुख से गाया है और महर्षि वेदव्यास ने संकलित किया है, इसलिए यह अत्यंत पवित्र ग्रंथ के रूप में पूजा जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं है, कि समय-समय पर अनेक संत-महन्त, ऋषि-मुनि, विद्वानों ने अपनी चेतना के अनुसार इसे परिभाषित किया है, इस संबंध में मैं बहुत स्पष्ट हूँ कि 'भगवान को अपना कार्य जिससे भी कराना है, वे अपने आप 'योग्य पात्र' खोज लेते हैं।'

जिस प्रकार भगवान ने स्वयं सारथी बनकर अर्जुन को खोजा और अपना कार्य उनसे कराया। यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भ्रम हो गया कि श्री कृष्ण वास्तव में भगवान हैं कि नहीं? क्यों कि वे आपस में बाल सखा थे। अर्जुन ने अपना भ्रम दूर करने के लिए प्रश्न किया है कि पहले तो आप ने कभी नहीं बताया कि आप भगवान है, तो भगवान ने कहा है सवाल 'रिसीवर' और ट्रांसमीटर का था, पहले बताता तो तुम नहीं समझ पाते, आज तुम्हारी परिस्थितियां ऐसी है कि तुम सब समझ सकते हो, अर्थात 'विषाद योग' सब कुछ रिसीव कर सकते हो, सम्पूर्ण 'भगवत गीत' यही है कि क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रशिक्षित कर रहे है।

मैं यह संदर्भ सिर्फ इसलिए लिया कि भगवान को अपना कार्य कराना है, तो वे अपना 'योग्य पात्र' खोज लेते हैं, उसी श्रेणी में श्री दिनेश एन वर्मा (खुशदिल)

चंद्र कुमार ऐडवोकेट

साहब हैं, स्वयं उन्हीं के शब्दों में 'संयोगवश, मेरे लिए काम आसान करने के लिए, मथुरा के एक विद्वान द्वारा लिखित हिंदी में गीता की व्याख्या का अंग्रेजी में अनुवाद करने का अवसर मेरे पास आया, जिसे मैंने किसी आर्थिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि इसके सिद्धांतों की बारीकियों को समझने के लिए लिया, आखिर क्या इस दुनिया में रह रहे आठ सौ करोड़ मानव आत्माओं में अंग्रेजी अनुबाद करने के लिए और कोई नहीं था? क्यों 'खुशदिल' साहब को ही चुना? क्योंकि उनके मन में जो बचपन से जो बीज प्रस्फुटित हो रहा था, वह अंकुरित होने के साथ-साथ समयानुसार पुष्पित-पल्लवित होता रहा और बाद में वटवृक्ष की शकल लेने लगा था। भगवान आपको बचपन से ही सिखाते आ रहे हैं, यह भी भगवत कृपा ही है कि आप को 'खुशदिल' बनाया।

'भगवत गीत' आज के जीवन शैली में आम आदमी की प्रबल आवश्यकता है शायद इसी लिए भगवान ने खुशदिल साहब को अंग्रेजी अनुबाद करने के बहाने से 'गीता में डूबने' का अवसर प्रदान किया, तभी यह 'भगवद गीता और आम आदमी' अंतर्मन से निकल कर बाहर आया। बगैर भगवत कृपा के यह असम्भव होता! यहां पर एक उदाहरण से और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आदि कवि महर्षि बाल्मीकि ने रामायण की मूल रचना संस्कृत में किया है, उसके अनेको अनुवाद हुए किन्तु कालांतर में जब गोस्वामी तुलसी दास जी ने आम आदमी की भाषा में उसकी रचना किया तो वह 'श्रीराम चरित मानस' के रूप में घर-घर में पहुंच गया। सम्भवतः खुशदिल साहब द्वारा लिखी गयी यह पुस्तक भी आम आदमी के लिए ही लिखी गयी है। वैसे तो यह पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गयी है किन्तु सहज व सरल है, यदि हिंदी में लिखा होता तो और भी उत्कृष्ट होता।

हमारे व्यक्तिगत समझ से जीवन के सभी मुद्दों का स्थाई समाधान 'भगवत गीता' है, इस किताब का सारांश है यह है कि, जीवन के किसी भी मुद्दों/समस्या को नजरअंदाज करने से भविष्य में दूरगामी दुखद परिणाम हो सकते हैं, किसी भी रोग का निदान तात्कालिक शमन नहीं, बल्कि उसका स्थाई निवारण होना जरुरी होता है, अन्यथा रोग कालांतर में बढ़ते-बढ़ते असाध्य रूप धारण कर लेता है, जो युक्तिहीन और खतरनाक सम्भावनाओं से भरपूर होता है, आज हमारे समाज में बहुआयामी समस्याएं है, जिससे छुटकारा पाने का निकट भविष्य में कोई आसार नजर नहीं आ रहा है, हमारा समाज राजनितिक, सामाजिक, संवैधानिक, कानूनी, नैतिक पतन से जूझ रहा है, ऐसे में यह किताब निश्चित रूप से समाज का मार्गदर्शन करने में एक विशेष औषधि का कार्य करेगा। खुशदिल साहब साधुवाद के पात्र है हमारी अनंत शुभकामनाएं।

(लेखक मीडिया मैप के प्रबंध संपादक हैं)

आध्यात्म की ओर एक व्यक्तिगत यात्रा

लेखक दिनेश वर्मा, भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपना समय लेखन को समर्पित किताब माई टाइम्स माई टेल्स प्रकाशित किया और वर्ष 2016 में उनकी पहली हुई जो 27, कहानियों का संग्रह है।

खोज के बारे में मेरे विचारों को नया आकार देती रही। मुख्य संदेश– कि जो लोग दर्द और सत्य की खोज में दुनिया को छोड़ देते हैं। वे भी अक्सर प्रेम और कर्तव्य के बंधन में लौट आते हैं हर गुजरते साल के साथ और अधिक गूंजता रहा। **–संपादक**

कई लोगों के लिए, भगवद गीता एक विस्मयकारी लेकिन अक्सर दुर्गम ग्रंथ है, जिसे पूजा जाता है, उद्धृत किया जाता है, और अनुष्ठानों में सम्मानित किया जाता है। फिर भी औसत व्यक्ति द्वारा शायद ही कभी सही मायने में समझा जाता है। मेरे मामले में, इस अंतर को पाटने की प्रेरणा विद्वानों की खोज से नहीं बल्कि एक गहरी व्यक्तिगत स्मृति से उभरी: एक कहानी जो मेरे दिवंगत पिता ने मुझे मेरे स्कूल के दिनों में 'शमशान वाले बाबा' के बारे में सुनाई थी– त्याग दुख और अंततः सांसारिक संबंधों में वापसी की कहानी।

जैसे–जैसे मैं बड़ी होती गई, वह कहानी मेरे दिमाग में घूमती रही, और चुपचाप जीवन, वैराग्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच शांति की शाश्वत। इस आंतरिक संवाद ने एक अहसास जगाया– अगर कोई व्यक्ति परिवार और सामाजिक प्रतिबद्धताओं से आसानी से दूर नहीं जा सकता, तो वह सांत्वना, मार्गदर्शन और आंतरिक संतुलन के लिए कहां जाए? इसका उत्तर, बादलों को चीरती हुई प्रकाश की किरण की तरह, भगवद

'भगवद् गीता को समझने की दिशा में' लिखना कोई आसान काम नहीं था। गीता के ज्ञान के रत्न जटिल दर्शन और दिव्य रूपक के धागों में जटिल रूप से बुने गए हैं। उनके सार को कम किए बिना व्यावहारिक निष्कर्ष निकालना सावधानीपूर्वक चिंतन की आवश्यकता थी। लेकिन जैसे-जैसे मैंने गहराई से जाना, एक दिलचस्प सच्चाई सामने आई ये सबक न केवल आध्यात्मिक हैं बल्कि गहराई से मानवीय भी हैं। वे आत्म प्रयास अनुशासन और आंतरिक लचीलेपन को प्रोत्साहित करते हैं कालातीत कहावत को प्रतिध्वनित करते हुए भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। दुनिया भर में लाखों लोग पूजा-पाठ करते हैं और पूजा-पाठ के स्थानों पर मंदिर मस्जिद, चर्च और आशीर्वाद, क्षमा और सांत्वना जाते हैं गुरुद्वारे पाने के लिए। फिर भी, बहुत से लोग ऐसा बिना यह समझे करते हैं कि वे किसकी या किसकी पूजा कर रहे हैं। मृत्यु का भय, परिवार के लिए चिंता और ईश्वरीय हस्तक्षेप की आशा इन भक्ति कार्यों को प्रेरित करती है। हालाँकि, गीता इस धारणा को चुनौती देती है।

गीता से आया- एक अमूर्त के रूप में नहीं, बल्कि जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक के रूप में।

यह 'भगवद्गीता को समझने की ओर' लिखने की मेरी यात्रा की शुरुआत थी गीता के गहन ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी के लिए प्रासंगिक, सुलभ अंतर्दृष्टि में बदलने का एक विनम्र प्रयास।

मेरे संकल्प को और मजबूत करने वाली बात यह थी कि आज हमारी दुनिया महाभारत के संघर्ष को दर्शाती है। जिस तरह पाँच पांडव सौ कौरवों के खिलाफ खड़े हुए थे, उसी तरह आधुनिक समाज अक्सर कलह, विवादों और घरेलू लड़ाइयों से घिरा हुआ महसूस करता है।

संपत्ति के झगड़े, टूटते रिश्ते और कानूनी झगड़े बहुत आम हो गए हैं। हालाँकि, पांडवों के विपरीत, हमारे पास हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण नहीं हैं। लेकिन गीता बनी हुई है- एक मौन लेकिन शक्तिशाली सहारा, जो ज्ञान प्रदान करता है जो दैनिक जीवन की अराजकता को दूर करने में मदद कर सकता है।

अपनी पूजनीय स्थिति के बावजूद न्यायालय में शपथ के लिए इस्तेमाल की जाने वाली और अंतिम संस्कारों तथा अनुष्ठानों में उद्धृत की जाने वाली गीता अभी भी आम लोगों द्वारा काफी हद तक अनपढ़ी जाती है। इसकी सहरी दार्शनिक कथा, जो अक्सर संस्कृत छंद्रों और विद्वानों की टिप्पणियों में लिपटी होती है, इसे पढ़ना डराने वाला बनाती है। जबकि संतों, विद्वानों और आध्यात्मिक साधकों ने इसकी गहराई का पता लगाया होगा, आम लोग अक्सर दूर से ही इसकी पवित्रता की प्रशंसा करते

रह जाते हैं, इस बात से अनजान कि यह कितनी स्पष्टता और साहस प्रदान कर सकती है।

इस अंतर को पाटने का अवसर मुझे अप्रत्याशित रूप से मिला, मधुरा के एक विद्वान द्वारा गीता पर हिंदी में की गई टिप्पणी का अनुवाद करने के अवसर के रूप में। इस प्रस्ताव में कोई आर्थिक लाभ नहीं था, लेकिन मैंने इसे पाठ को और अधिक गहराई से समझने की गंभीर इच्छा के साथ स्वीकार किया। जैसे-जैसे मैंने अठारह अध्यायों में प्रत्येक श्लोक और उसकी व्याख्या पर काम किया, मैंने खुद को एक ऐसी दुनिया में डूबा हुआ पाया जहाँ आध्यात्मिकता मनोविज्ञान से मिलती है, और शाश्वत सत्य रोज़मर्रा के संघर्षों को दर्शाते हैं।

उस गहन अनुभव ने एक नए दृष्टिकोण की नींव रखी- गीता की व्याख्या रहस्यवाद के चश्मे से नहीं, बल्कि आम लोगों के अनुभवों के माध्यम से की गई। लक्ष्य सरल था- ऐसी भाषा में बात करना जिसे आम लोग समझ सकें, संबंधित स्थितियों और व्यावहारिक अनुप्रयोगों का उपयोग करना।

'गीता जैसी है' एक एक स्मारकीय स्मारकीय कृति बनी हुई है, लेकिन कई लोगों के लिए, इसका उच्च आध्यात्मिक प्रवचन दूर की कौड़ी लग सकता है। सैरा प्रयास एक ऐसा संस्करण लिखना है जो औसत बुद्धि रोज़मर्रा की चिंताओं और शांति की इच्छा रखने वालों से बात करे, शायद ज्ञान की नहीं, बल्कि जीवन की परीक्षाओं का सामना करने के लिए संतुलन और शक्ति की।

'भगवद् गीता को समझने की दिशा में' लिखना कोई आसान काम नहीं था। गीता के ज्ञान के रत्न जटिल दर्शन और दिव्य रूपक के धागों में जटिल रूप से बुने गए हैं। उनके सार को कम किए बिना व्यावहारिक निष्कर्ष निकालना सावधानीपूर्वक चिंतन की आवश्यकता थी। लेकिन जैसे-जैसे मैंने गहराई से जाना, एक दिलचस्प सच्चाई सामने आई ये सबक न केवल आध्यात्मिक हैं बल्कि गहराई से मानवीय भी हैं। वे आत्म प्रयास अनुशासन और आंतरिक लचीलेपन को प्रोत्साहित करते हैं कालातीत कहावत को प्रतिध्वनित करते हुए भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं।

दुनिया भर में लाखों लोग पूजा-पाठ करते हैं और पूजा-पाठ के स्थानों

पर मंदिर मस्जिद, चर्च और आशीर्वाद, क्षमा और सांत्वना जाते हैं गुरुद्वारे पाने के लिए। फिर भी, बहुत से लोग ऐसा बिना यह समझे करते हैं कि वे किसकी या किसकी पूजा कर रहे हैं। मृत्यु का भय, परिवार के लिए चिंता और ईश्वरीय हस्तक्षेप की आशा इन भक्ति कार्यों को प्रेरित करती है। हालाँकि, गीता इस धारणा को चुनौती देती है। अपनी उज्ज्वल शिक्षाओं के माध्यम से, यह प्रकट करती है कि बिना समझ के पूजा खोखली है, और सच्ची भक्ति ईमानदारी आत्म-जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जीने में निहित है।

गीता को अक्सर आध्यात्मिक पुस्तक के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी सार्वभौमिक प्रासंगिकता में निहित है। भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई इसकी शिक्षाएँ अक्सर दिव्य आख्यान में लिपटी होती हैं, लेकिन उनका सार पूरी मानवता पर लागू होता है। संवाद प्रारूप मानवीय ज्ञान में दिव्य भार जोड़ता है, जिससे यह पवित्र और लागू दोनों हो जाता है।

आत्म-अनुशासन, कर्तव्य और परिणामों से विरक्ति जैसे गुणों पर जोर देकर, गीता आदर्श मानव की तस्वीर पेश करती है-संतुलित दृढ़ निश्चयी और दयालु। यह उदासीनता नहीं, बल्कि कर्म करने की प्रेरणा देती है- अंध कर्मकांड नहीं, बल्कि जागरूकता की प्रेरणा देती है।

मेरा काम गीता की विद्वत्तापूर्ण पुनर्व्याख्या नहीं है। इससे कहीं दूर। मैं कोई दार्शनिक या रहस्यवादी नहीं हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, जो दूसरे आम पुरुषों और महिलाओं को संबोधित करता हूँ। मेरा लक्ष्य गेहूँ को भूसे से अलग करना और गीता का ऐसा संस्करण प्रस्तुत करना है जो चुनौतीपूर्ण दुनिया में शांतिपूर्ण, सार्थक जीवन जीने के लिए उपकरण प्रदान करता है।

ऐसा करने में, मैं उन लोगों को एक छोटी सी रोशनी प्रदान करने की आशा करता हूं जो स्पष्टता की तलाश कर रहे हैं, त्याग के जंगलों में नहीं, बल्कि घरों, कार्यालयों और रिश्तों में जहां जीवन वास्तव में प्रकट होता है।

गीता को अक्सर आध्यात्मिक पुस्तक के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी सार्वभौमिक प्रासंगिकता में निहित है। भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई इसकी शिक्षाएँ अक्सर दिव्य आख्यान में लिपटी होती हैं, लेकिन उनका सार पूरी मानवता पर लागू होता है। संवाद प्रारूप मानवीय ज्ञान में दिव्य भार जोड़ता है, जिससे यह पवित्र और लागू दोनों हो जाता है। आत्म-अनुशासन, कर्तव्य और परिणामों से विरक्ति जैसे गुणों पर जोर देकर, गीता आदर्श मानव की तस्वीर पेश करती है-संतुलित दृढ़ निश्चयी और दयालु। यह उदासीनता नहीं, बल्कि कर्म करने की प्रेरणा देती है- अंध कर्मकांड नहीं, बल्कि जागरूकता की प्रेरणा देती है। मेरा काम गीता की विद्वत्तापूर्ण पुनर्व्याख्या नहीं है। इससे कहीं दूर। मैं कोई दार्शनिक या रहस्यवादी नहीं हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, जो दूसरे आम पुरुषों और महिलाओं को संबोधित करता हूँ। मेरा लक्ष्य गेहूँ को भूसे से अलग करना और गीता का ऐसा संस्करण प्रस्तुत करना है जो चुनौतीपूर्ण दुनिया में शांतिपूर्ण, सार्थक जीवन जीने के लिए उपकरण प्रदान करता है।

- संपत्ति के झगड़े, टूटते रिश्ते और कानूनी झगड़े बहुत आम हो गए हैं। हालाँकि, पांडवों के विपरीत, हमारे पास हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण नहीं हैं। लेकिन गीता बनी हुई है- एक मौन लेकिन शक्तिशाली सहारा, जो ज्ञान प्रदान करता है जो दैनिक जीवन की अराजकता को दूर करने में मदद कर सकता है।

- अपनी पूजनीय स्थिति के बावजूद न्यायालय में शपथ के लिए इस्तेमाल की जाने वाली और अंतिम संस्कारों तथा अनुष्ठानों में उद्धृत की जाने वाली गीता अभी भी आम लोगों द्वारा काफी हद तक अनपढ़ी जाती है। इसकी सहरी दार्शनिक कथा, जो अक्सर संस्कृत छंदों और विद्वानों की टिप्पणियों में लिपटी होती है, इसे पढ़ना डराने वाला बनाती है।

- संतों, विद्वानों और आध्यात्मिक साधकों ने इसकी गहराई का पता लगाया होगा, आम लोग अक्सर दूर से ही इसकी पवित्रता की प्रशंसा करते रह जाते हैं, इस बात से अनजान कि यह कितनी स्पष्टता और साहस प्रदान कर सकती है।

- इस अंतर को पाटने का अवसर मुझे अप्रत्याशित रूप से मिला, मधुरा के एक विद्वान द्वारा गीता पर हिंदी में की गई टिप्पणी का अनुवाद करने के अवसर के रूप में। इस प्रस्ताव में कोई आर्थिक लाभ नहीं था, लेकिन मैंने इसे पाठ को और अधिक गहराई से समझने की गंभीर इच्छा के साथ स्वीकार किया। जैसे-जैसे मैंने अठारह अध्यायों में प्रत्येक श्लोक और उसकी व्याख्या पर काम किया, मैंने खुद को एक ऐसी दुनिया में डूबा हुआ पाया जहाँ आध्यात्मिकता मनोविज्ञान से मिलती है, और शाश्वत सत्य रोजमर्रा के संघर्षों को दर्शाते हैं।

पहले टेस्ट के लिए मंच तैयार : सभी की निगाहें टीम संयोजन पर

20 जून से लीड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट के लिए मंच सज चुका है, और अब सबका ध्यान भारत की अंतिम एकादश के संयोजन पर है।

इंग्लैंड भारतीय क्रिकेट के लिए हमेशा एक अलग तरह की चुनौती पेश करता है–ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका से अलग–गर्मी की शुरुआत में ठंडा मौसम और सीमिंग पिचें, जो ऑस्ट्रेलिया की कठोर उछालभरी या भारत की धीमी समतल पिचों से बिल्कुल भिन्न हैं। यह वास्तव में तकनीक की परीक्षा बन जाता है, जो कि टेस्ट क्रिकेट की बुनियादी मांग है– जैसा कि टी20 की तेज़ और धमाकेदार शैली से उलट। इसलिए आईपीएल और टी20 में प्रदर्शन का यहां कोई विशेष महत्व नहीं होना चाहिए और उसे मानदंड नहीं बनाना चाहिए।

सलामी बल्लेबाज़ों को लेकर कोई बहस नहीं होनी चाहिए– जैसवाल और राहुल। इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया में एक साथ अच्छा प्रदर्शन किया था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल को कोहली की जगह नंबर 4 पर खेलना चाहिए क्योंकि वह टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज़ हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अच्छी शुरुआत हमेशा महत्वपूर्ण होती है और विदेशी सरज़मीं पर राहुल का रिकॉर्ड पिछले 5 वर्षों में किसी भी अन्य भारतीय बल्लेबाज़, यहां तक कि रोहित और विराट से बेहतर रहा है– साथ ही उनकी 8 में से 7 टेस्ट सेंचुरी ओपनर के रूप में आई हैं। जैसवाल का यह इंग्लैंड का पहला दौरा है और भले ही उनमें प्रतिभा और हालिया

अनिल जौहरी

♦♦

इंग्लैंड भारतीय क्रिकेट के लिए हमेशा एक अलग तरह की चुनौती पेश करता है- ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका से अलग- गर्मी की शुरुआत में ठंडा मौसम और सीमिंग पिचें, जो ऑस्ट्रेलिया की कठोर उछालभरी या भारत की धीमी समतल पिचों से बिल्कुल भिन्न हैं। यह वास्तव में तकनीक की परीक्षा बन जाता है, जो कि टेस्ट क्रिकेट की बुनियादी मांग है- जैसा कि टी20 की तेज़ और धमाकेदार शैली से उलट। इसलिए आईपीएल और टी20 में प्रदर्शन का यहां कोई विशेष महत्व नहीं होना चाहिए और उसे मानदंड नहीं बनाना चाहिए। सलामी बल्लेबाज़ों को लेकर कोई बहस नहीं होनी चाहिए- जैसवाल और राहुल। इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया में एक साथ अच्छा प्रदर्शन किया था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल को कोहली की जगह नंबर 4 पर खेलना चाहिए क्योंकि वह टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज़ हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अच्छी शुरुआत हमेशा महत्वपूर्ण होती है और विदेशी सरज़मीं पर राहुल का रिकॉर्ड पिछले 5 वर्षों में किसी भी अन्य भारतीय बल्लेबाज़, यहां तक कि रोहित और विराट से बेहतर रहा है- साथ ही उनकी 8 में से 7 टेस्ट सेंचुरी ओपनर के रूप में आई हैं। जैसवाल का यह इंग्लैंड का पहला दौरा है और भले ही उनमें प्रतिभा और हालिया रिकॉर्ड हो, यह उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, इसलिए उनके साथ किसी नए सलामी बल्लेबाज़ को उतारना जोखिम भरा होगा।

♦♦

रिकॉर्ड हो, यह उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, इसलिए उनके साथ किसी नए सलामी बल्लेबाज़ को उतारना जोखिम भरा होगा। नंबर 3 पर गिल को उतारना चाहिए– यही वह स्थान है जहां वह कुछ समय से बल्लेबाज़ी कर रहे हैं और यह स्थान भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि वह अब तक अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए हैं, लेकिन जब तक वह कप्तान होने के नाते अपने क्रम को बदलने का विशेषाधिकार नहीं लेते, इस क्रम को छेड़ना नहीं चाहिए।

नंबर 4 के लिए करुण नायर फिलहाल सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं– अपेक्षाकृत अनुभवी और अच्छे फॉर्म में। अगर ईश्वरन को बैकअप ओपनर के रूप में चुना गया था, तो साई सुदर्शन नंबर 5 के लिए एकमात्र दावेदार रह जाते हैं। क्या ध्रुव जुरेल इंग्लैंड में दिखाए शुरुआती फॉर्म के कारण मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज़ के रूप में उम्मीदवार हो सकते हैं? संभव है, लेकिन लगता है कि टीम प्रबंधन साई सुदर्शन के साथ जाएगा। वैसे भी, पंत उपकप्तान के रूप में निश्चित हैं और विकेट कीपर की भूमिका उन्हीं के पास रहेगी।

इसके बाद पंत के बाद नितीश रेड्डी और जडेजा ऑलराउंडर के रूप में उतरने चाहिएं। हालांकि ठाकुर भी पेस ऑलराउंडर की दौड़ में हैं, लेकिन पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे में रेड्डी के प्रदर्शन और चयन में निरंतरता को देखते हुए उन्हें मौका मिलना चाहिए।

क्या भारत को स्पिन में कुलदीप यादव पर दांव लगाना चाहिए? जडेजा की जगह? शायद ओवल में, लेकिन लीड्स में नहीं। इसके बाद आते हैं तीन तेज गेंदबाज़– बुमराह और सिराज को लेकर कोई बहस नहीं है। तीसरे स्लॉट के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह में मुकाबला है, और मेरी राय में अर्शदीप को मौका मिलना चाहिए–वह बाएं हाथ के गेंदबाज़ होने के कारण विविधता लाते हैं और सीमिंग पिचों के लिए अधिक उपयुक्त हैं, जबकि लंबे कद वाले प्रसिद्ध कठिन पिचों पर बेहतर विकल्प हो सकते हैं।

पहले टेस्ट के लिए लीड्स जैसे स्थान का चयन यह स्पष्ट संकेत देता है कि इंग्लैंड शुरुआत से ही भारत को बैकफुट पर धकेलना चाहता है क्योंकि यह इंग्लैंड की सबसे अधिक सीम-मित्र पिचों में से एक है। रोहित और विराट की अनुपस्थिति में भारत की बल्लेबाज़ी थोड़ी अनुभवहीन दिखती है और शमी की गैरमौजूदगी में गेंदबाज़ी भी कुछ कमजोर नजर आती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस गर्मी में भारतीय टीम को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा।

टेस्ट टीम चयन : कुछ सवाल अब भी अनुत्तरित : आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की 5 टेस्ट मैचों की टीम घोषित कर दी गई है– शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान और विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल, के.एल. राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नितीश रेड्डी, रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव।

चयन की विश्लेषण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कुछ समय तक चलेगी भी। भारतीय चयनकर्ताओं का काम निश्चित रूप से जटिल और अकृतज्ञता से भरा होता है। फिर भी, यह अपेक्षा की जाती है कि जब वे इस स्तर तक पहुंचे हैं, तो वे अपने कार्य में सक्षम हों और चयन प्रदर्शन, प्रतिभा, ठोस तर्क और निरंतरता के आधार पर करें।

इंग्लैंड दौरे के लिए चुनी गई भारतीय टीम का मूल्यांकन इन्हीं मानदंडों पर किया जाना चाहिए।

♦♦

चयन की विश्लेषण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कुछ समय तक चलेगी भी। भारतीय चयनकर्ताओं का काम निश्चित रूप से जटिल और अकृतज्ञता से भरा होता है। फिर भी, यह अपेक्षा की जाती है कि जब वे इस स्तर तक पहुंचे हैं, तो वे अपने कार्य में सक्षम हों और चयन प्रदर्शन, प्रतिभा, ठोस तर्क और निरंतरता के आधार पर करें। इंग्लैंड दौरे के लिए चुनी गई भारतीय टीम का मूल्यांकन इन्हीं मानदंडों पर किया जाना चाहिए। क्या दिखता है : जहाँ ओपनरों (जायसवाल, राहुल और बैकअप के रूप में ईश्वरन) या स्पिनरों (जडेजा, सुंदर और यादव) के चयन पर विवाद नहीं किया जा सकता, वहीं बाकी चयन में कई सवाल हैं। दृष्टिकोण : आजकल क्रिकेट के कई प्रारूप - टेस्ट, वनडे, टी20-और वो भी घरेलू व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक साथ चल रहे हैं। ऐसे में चयन करते समय सब पर नज़र रखना और प्रारूपों के बीच सही अंतर करना कठिन है। इसके अलावा, हालिया प्रदर्शन से प्रभावित होना और लंबे समय के प्रदर्शन को अनदेखा करना भी एक समस्या है। शुभमन गिल को पंत के ऊपर कप्तान बनाए जाने में भी यही हुआ है। आईपीएल प्रदर्शन और टीम के प्रदर्शन के आधार पर गिल को बेहतर माना गया, यह भूलते हुए कि टी20 में कोच और डगआउट की भूमिका बड़ी होती है और वह कप्तानी के असली कौशल की कसौटी नहीं होती।

♦♦

क्या दिखता है :

जहाँ ओपनरों (जायसवाल, राहुल और बैकअप के रूप में ईश्वरन) या स्पिनरों (जडेजा, सुंदर और यादव) के चयन पर विवाद नहीं किया जा सकता, वहीं बाकी चयन में कई सवाल हैं।

दृष्टिकोण (Optics) :

आजकल क्रिकेट के कई प्रारूप-टेस्ट, वनडे, टी20-और वो भी घरेलू व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक साथ चल रहे हैं। ऐसे में चयन करते समय सब पर नज़र रखना और प्रारूपों के बीच सही अंतर करना कठिन है। इसके अलावा, हालिया प्रदर्शन से प्रभावित होना और लंबे समय के प्रदर्शन को अनदेखा करना भी एक समस्या है।

शुभमन गिल को पंत के ऊपर कप्तान बनाए जाने में भी यही हुआ है। आईपीएल प्रदर्शन और टीम के प्रदर्शन के आधार पर गिल को बेहतर माना गया, यह भूलते हुए कि टी20 में कोच और डगआउट की भूमिका बड़ी होती है और वह कप्तानी के असली कौशल की कसौटी नहीं होती।

गिल का विदेशी टेस्ट औसत केवल 27.5 है (15 टेस्ट में), जबकि घरेलू टेस्ट में 42। इंग्लैंड में उनके पिछले दौरे में उन्होंने 3 टेस्ट में कुल 88 रन बनाए थे। क्या वह बल्लेबाजी क्रम में निश्चित रूप से फिट बैठते हैं- शायद नहीं।

वहीं पंत के आंकड़े बेहतर हैं- इंग्लैंड में 9 टेस्ट में औसत 32, और कुल विदेशी टेस्ट में औसत 37 (30 टेस्ट में)। और वह टीम में गिल से कहीं ज्यादा निश्चित खिलाड़ी हैं।

निरंतरता (Consistency) :

सरफराज को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर स्क्वाड में रखा गया था-बावजूद इसके कि बल्लेबाजी बार-बार फेल हुई, उन्हें एक भी मौका नहीं दिया गया। और अब उन्हें स्क्वाड से ही बाहर कर दिया गया है। इसी तरह, पड्डीकल को भी स्क्वाड से बाहर लाकर एक टेस्ट में खिलाया गया था और बाद में हटा दिया गया-अब वे 18 सदस्यीय दल में भी नहीं हैं। एक टेस्ट का प्रदर्शन किसी खिलाड़ी के मूल्यांकन का मापदंड नहीं हो सकता। चयनकर्ताओं में चयन के बाद खिलाड़ियों के साथ एकसमान रवैया होना चाहिए-जो इन मामलों में नहीं दिखता।

तर्क (Logic) :

ऑस्ट्रेलिया में भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी-निस्संदेह बल्लेबाजी! और अब रोहित और विराट के संन्यास के बाद यह और भी कमज़ोर लग रही है।

इसके बावजूद, टीम में 7 तेज गेंदबाज़ और केवल 3 मध्यक्रम

बल्लेबाज़ (गिल, साई, नायर) हैं! ओपनरों (जायसवाल, राहुल, ईश्वरन) को गिनें तो भी मध्यक्रम के लिए कोई बैकअप नहीं है। अगर कोई बल्लेबाज फ्लॉप हो जाता है तो बैकअप कौन होगा?

तेज़ गेंदबाज़ी विभाग देखें- अंतिम 11 में कितने गेंदबाज़ खिलाएंगे? आदर्श रूप से 3 तेज गेंदबाज़ (बुमराह/सिराज/अर्शदीप), एक ऑलराउंडर (रेड्डी) और एक स्पिनर (जडेजा)।

अगर पिच स्पिन को मदद करे, तो एक तेज गेंदबाज़ कम करके एक और स्पिनर (यादव या सुंदर) लिया जा सकता है। तो फिर बैकअप के लिए प्रसिद्ध, आकाश दीप और ठाकुर-तीन तेज़ गेंदबाज़ क्यों? क्या हम एक या दो तेज गेंदबाज़ ज़्यादा और एक मध्यक्रम बल्लेबाज़ कम नहीं ले गए?

इसके अलावा, अगर पंत प्लेइंग 11 में निश्चित हैं, तो फिर एक और विकेटकीपर (जुरेल) रखने का क्या तुक? राहुल बैकअप विकेटकीपर हो सकते थे-इससे एक स्लॉट बचता, जिसमें हम एक विशेषज्ञ बल्लेबाज़ रख सकते थे।

बुमराह से कप्तानी इसलिए छीनी गई क्योंकि वे 5 टेस्ट खेलने को लेकर निश्चित नहीं थे-चोट और वर्कलोड की वजह से। तो यही तर्क शमी पर क्यों नहीं लागू किया गया? शमी के बारे में कोई स्पष्ट सूचना नहीं आई कि वे फिट नहीं हैं या लंबे समय के लिए बाहर हैं। अगर वे खेलने के लिए फिट हैं तो टीम में शामिल किए जाने चाहिए थे और उनका वर्कलोड भी मैनेज किया जा सकता था।

प्रदर्शन (Performance) :

करुण नायर को घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनाम दिया गया है-यह सराहनीय है। लेकिन यही मापदंड श्रेयस अय्यर पर क्यों लागू नहीं हुआ, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में निरंतर अच्छा प्रदर्शन किया?

इन सभी बातों से लगता है कि चयनकर्ता इससे बेहतर चयन कर सकते थे। इंग्लैंड वैसे भी एक कठिन दौरा होता है। टीम में सही संतुलन न होना समस्याओं को और बढ़ा सकता है। उम्मीद है कि गिल बल्लेबाज के रूप में सफल होंगे और इस साल की शुरुआत में सिडनी में जो हुआ (जब कप्तान को खुद को बाहर करना पड़ा) वह दोबारा नहीं होगा।

उम्मीद है कि मध्यक्रम भी चलेगा और हमें बैकअप की कमी का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। हमें टीम को शुभकामनाएं देनी चाहिए और आशा करनी चाहिए कि वह इस कठिन सीरीज को जीतकर लौटे।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मंत्री विजय शाह पर एफआईआर का अभूतपूर्व आदेश

सोफिया कुरेशी

जब सत्ताधारी राजनीतिक दल के मंत्री अराजक हो जाते हैं तब उनके खिलाफ राजनीतिक दल से तो किसी कड़ी कार्यवाही की उम्मीद बेकार है, ऐसे में पुलिस प्रशासन भी हिम्मत नहीं जुटा पाता।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेकर इस मामले में एफ आई आर का निर्देश दिया है, यह आदेश अभूतपूर्व नजीर बनना चाहिए जिसे अन्य उच्च न्यायालय भी संज्ञान में ले सकते हैं और भविष्य में पुलिस प्रशासन भी इससे हिम्मत जुटा सकती है।

मध्य प्रदेश के उन सभी मतदाताओं को भी शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी जिन्होंने ऐसे व्यक्ति को अपना जन प्रतिनिधि चुना है। बेलगाम हुई सत्ता पर नियंत्रण के लिए उम्मीद की बड़ी किरण है यह फैसला।

विजय शाह की अभद्र टिप्पणी पर बीजेपी हाईकमान कब लेगी एक्शन?

देश की बेटी और सेना की शान पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह पर आखिर कब होगी कड़ी कार्रवाई?

पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी और स्कूल की बेटियों के साथ अभद्रता कर चुके मंत्री को क्या मोहन यादव मंत्रिमंडल से करेंगे बर्खास्त?

हाईकोर्ट का DGP को आदेश, मंत्री विजय शाह पर करें FIR.

विजया पाठक, एडिटर, जगत विजन

मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने देश के गौरव के साथ अखण्डता और एकता पर वार किया है। उन्होंने ना सिर्फ बीजेपी को बल्कि भारतीय फौज को भी अपमानित किया है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भारतीय संस्कृति को मिट्टी में मिलाने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री पर कार्रवाई कर देश के सामने एक मिसाल पेश करे। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने की कोशिश करने वाले प्रदेश के मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह की कर्नल सौफिया कुरैशी पर की गई अभद्र टिप्पणी ने पूरे महिला समाज को शर्मसार कर दिया है। शाह के इस बयान ने न सिर्फ समाज के महिला वर्ग की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया है बल्कि उन्होंने देश की सीमा पर तैनात रहने वाली उन लाखों महिलाओं और बेटियों पर अभद्र टिप्पणी की है। विजय शाह की इस टिप्पणी ने जहां भारतीय जनता पार्टी की महिला सम्मान की संस्कृति को तार-तार कर दिया है बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के महिला सैनिकों के सम्मान और वीरता के लिए दिये गये उस सलाम को भी मिट्टी में मिला दिया है जो उन्होंने दो दिन पहले राष्ट्र के संबोधन के नाम पर दी थी। समझने वाली बात यह है कि भ्रष्टाचारी और दुराचारी मंत्री विजय शाह के दिमाग में गंदगी के अलावा क्या कुछ नहीं है। यह पहला अवसर नहीं है जब शाह ने इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दिया हो इससे पहले भी विजय शाह झूठी पब्लिसिटी पाने के लिए फालतू के बयान देते रहे हैं।

देश और प्रदेश की बेटी पर उठाया सवाल

विजय शाह ने इंदौर जिले के मानपुर क्षेत्र के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा पहले तो पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा, हर झोपड़ी और हर खोपड़ी में हलमा होना चाहिए, हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे हैं, समाज के लिए जान लगा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वह कटे-पिटे लोगों को, हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई।

आतंकवादियों ने कपड़े उतार-उतारकर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी-तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर भेजा। मोदी जी कपड़े उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की

बहन को भेजा, कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारी समाज की बहन आकर के पाले खोल के छोड़ेगी।

डैमेज कंट्रोल की कोशिश न करे भाजपा बल्कि इस्तीफा ले

देश की बेटियों पर इस तरह के अभद्र किस्म की टिप्पणी करने वाला यह नालायक मंत्री विजय शाह को मोहन सरकार को तत्काल प्रभाव से कैबिनेट से बाहर कर देना चाहिए। यही नहीं राष्ट्रीय महिला आयोग को एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग को विजय शाह का विधायक पद समाप्त करने की सिफारिश करना चाहिए। कुल मिलाकर डॉ. मोहन यादव से लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक हर किसी को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और विजय शाह की राजनीतिक यात्रा पर तत्काल प्रभाव से ब्रेक लगाना चाहिए। क्योंकि यह समय डेमेज कंट्रोल का नहीं है बल्कि यह समय फैसला लेने का है अगर भाजपा, सत्ता और संगठन शाह के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करते हैं तो निश्चित ही यह फैसला अन्य राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए एक बड़ा सबक होगा। क्योंकि जो नेता मां-बेटियों और बहनों की इज्जत नहीं करता उसे इस देश और प्रदेश में सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं है।

कुत्ते की पूछ की तरह है विजय शाह की चाल

देखा जाये तो विजय शाह के विवादित बयान उस कुत्ते की पूछ की तरह है जिसे 12 साल पोंगली में रखे तो भी वह निकलने के बाद तिरछी ही निकलेगी। ऐसा ही है विजय शाह का चरित्र। इससे पहले शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह चौहान को लेकर विवादित बयान दिया था जिसके बाद चौहान ने तत्काल प्रभाव से शाह से इस्तीफा लेकर उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। उसके बाद शाह ने स्कूल शिक्षा मंत्री रहते हुए एक समारोह में स्कूल की लड़कियों पर भद्दी टिप्पणी की थी जिसके बाद भी भाजपा और सत्ता, संगठन ने कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। यही कारण है कि शाह को दोनों ओर से बराबर ढील मिलती चली गई और वह इस तरह की अभद्रता भरी बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं।

विजय शाह को मिले ऐसी सजा, जो बने मिसाल

एक महिला पत्रकार होने के नाते मैं यही चाहूंगी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और गृहमंत्री अमित शाह तीनों मिलकर विजय शाह की इस अभद्रता पर कार्रवाई वोट की राजनीति से उठकर करें तो निश्चित तौर पर वह एक मिसाल बनेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा निर्णय लेकर शाह को बर्खास्त कर दिया तो यह फैसला आने वाले कई वर्षों तक लोगों की स्मृति में बना रहेगा और दोबारा कोई गंवार नेता इस तरह की अभद्रता भरे बयान नहीं देगा।

कोर्ट का आदेश, शाह पर दर्ज करें एफआईआर

मंत्री विजय शाह पर एफआईआर की जाएगी। हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है। डीजीपी को मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। 'ऑपरेशन सिंदूर' से सुर्खियों में आई कर्नल सोफिया को लेकर मंत्री ने टिप्पणी की थी। उन्हें आतंकियों का रिश्तेदार बता दिया था, जिसके बाद मंत्री के बयान के खिलाफ विरोध के स्वर उठे थे। आपत्तिजनक बयान पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया। जबलपुर की खंडपीठ ने स्वप्रेरणा विजय शाह पर गंभीर आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। ◆◆

देश की बेटियों पर इस तरह के अभद्र किस्म की टिप्पणी करने वाला यह नालायक मंत्री विजय शाह को मोहन सरकार को तत्काल प्रभाव से कैबिनेट से बाहर कर देना चाहिए। यही नहीं राष्ट्रीय महिला आयोग को एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग को विजय शाह का विधायक पद समाप्त करने की सिफारिश करना चाहिए। कुल मिलाकर डॉ. मोहन यादव से लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक हर किसी को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और विजय शाह की राजनीतिक यात्रा पर तत्काल प्रभाव से ब्रेक लगाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है। डीजीपी को मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। 'ऑपरेशन सिंदूर' से सुर्खियों में आईं कर्नल सोफिया को लेकर मंत्री ने टिप्पणी की थी। उन्हें आतंकियों का रिश्तेदार बता दिया था, जिसके बाद मंत्री के बयान के खिलाफ विरोध के स्वर उठे थे। आपत्तिजनक बयान पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। जबलपुर की खंडपीठ ने स्वप्रेरणा विजय शाह पर गंभीर आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज करने के निर्देश दिये हैं।

हम सब एक हैं - डार्विन की वैज्ञानिक चेतना आज और ज़रूरी है

धर्मेन्द्र आज़ाद

उन्नीसवीं सदी में जब तमाम धार्मिक कथाएं यह दावा कर रही थीं कि जीवन किसी ईश्वर की विशेष रचना है, तब चार्ल्स डार्विन ने विज्ञान की मशाल लेकर वह रास्ता दिखाया जिससे हम खुद को और इस दुनिया को सच में समझ सकें। उन्होंने यह स्थापित किया कि हम सब–मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़–पौधे, कीटाणु–एक ही विकास–श्रृंखला की कड़ियां हैं। कोई जन्म से श्रेष्ठ नहीं, कोई नीच नहीं। हम सब एक ही जैविक प्रक्रिया की संतान हैं।

डार्विन का विकासवाद कोई मत नहीं, बल्कि वैज्ञानिक यथार्थ है।

1831 में 'एचएमएस बीगल' से शुरू हुई उनकी यात्रा सिर्फ भौगोलिक नहीं थी– वह एक बौद्धिक क्रांति, जीव विकास को वैज्ञानिक तरीक़े से देखने की शुरुआत थी। गैलापागोस द्वीपों पर पक्षियों की चोंचों में अंतर देखकर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जीव–जंतु स्थिर नहीं हैं, वे अपने पर्यावरण के अनुसार बदलते रहते हैं। इसी से उन्होंने 'प्राकृतिक वरण' (Natural Selection) का सिद्धांत प्रतिपादित किया जो जीव अपने परिवेश के अनुरूप होता है, वही जीवित रहता है और अपनी संतति को आगे बढ़ाता है। यह सोच सिर्फ एक वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं थी– यह धार्मिक सत्ता और नस्लीय–जातिगत श्रेष्ठता के दावों के खिलाफ सीधी चुनौती थी। डार्विन ने दिखाया कि कोई 'ऊपर से भेजा गया विशेष प्राणी' नहीं होता। नस्ल, जाति, धर्म, लिंग, रंग–ये सब सामाजिक कल्पनाएं हैं, जैविक सच्चाई नहीं।

- प्रकृति के नजरिए से हम सब बराबर हैं– और धरती पर सबका समान अधिकार है।
- और आज भारत में हो क्या रहा है? जब स्कूलों के पाठ्यक्रम से डार्विन के सिद्धांत को हटाया जाता है, जब बच्चों को यह सिखाया जाता है कि 'हमें ब्रह्मा या किसी देवी–देवता ने बनाया।' तब यह हमला केवल डार्विन पर नहीं होता– यह हमला होता है तर्क पर, विज्ञान पर, और मनुष्य की गरिमा पर। जो सरकारें विज्ञान के स्थान पर धार्मिक मिथकों को थोपना चाहती हैं।
- वे एक ऐसे समाज की नींव रख रही हैं जहाँ वैज्ञानिक सोच को दबाया जाए।
- जहाँ वर्ण व्यवस्था को 'पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम' बताकर उसे और भी मजबूत किया जाए। जहाँ इंसान को धर्म, जाति और अंधश्रद्धा के दलदल से बाहर न निकलने दिया जाए। लेकिन डार्विन की वैज्ञानिक विरासत इस अंधकार के ख़िलाफ़ रोशनी है।
- डार्विन हमें याद दिलाते हैं कि कोई मनुष्य ऊँचा नहीं, कोई नीचा नहीं।
- कोई जन्म से महान नहीं, कोई अभागा नहीं।
- हम सब एक ही विकास की यात्रा के साथी हैं– प्रकृति की समान संतानें।
- डार्विन को याद करना आज का वैज्ञानिक संघर्ष है।
- यह तर्क, समानता और चेतना की उस परंपरा को आगे ले जाना है।
- जो हर बच्चे, हर जीव, हर समुदाय को इस धरती पर समान अधिकार और सम्मान देने की बात करता है।
- क्योंकि यह धरती किसी एक जाति, धर्म या वर्ग की जागीर नहीं– यह धरती सबकी है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

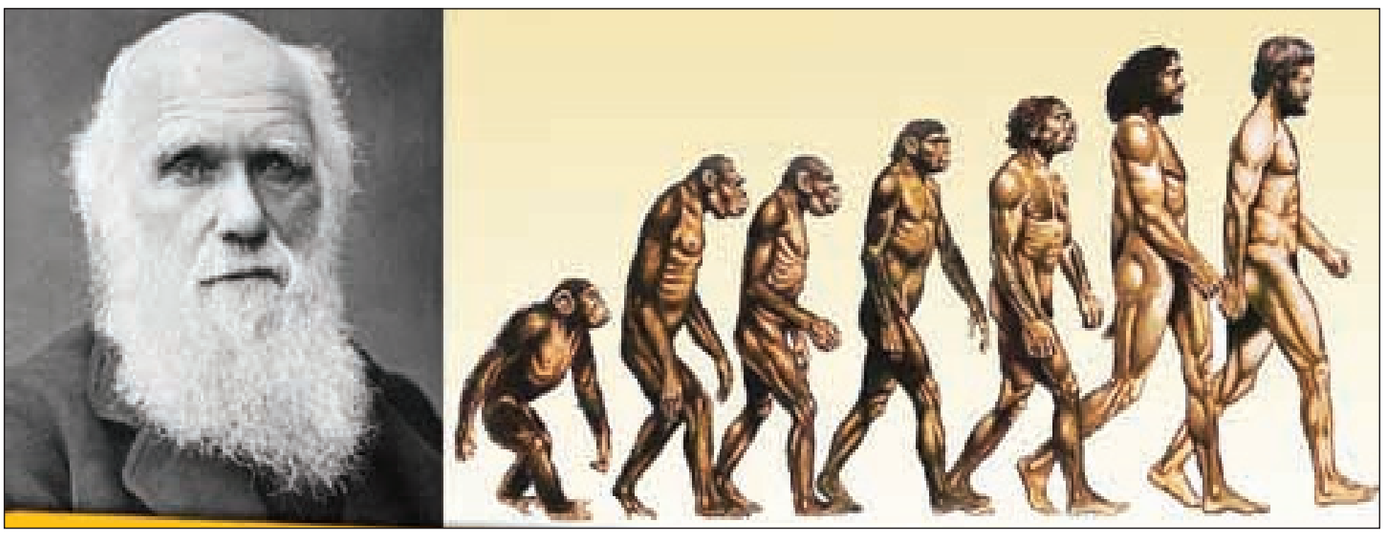

हास्य व्यंग

एक उभरते नेता का इतिहास बोध

प्रो. प्रदीप माथुर

जमुना प्रसाद जी मेरे पड़ोसी है। सरकारी सेवा से रिटायर होकर पिछले साल उन्होंने मेरी लाइन में किनारे वाला मकान खरीदा और उनके गृह प्रवेश की पूजा के उपलक्ष में सारे पड़ोस के लोगों को बुलाया। मैं ना जा सका तो शाम को प्रसाद लेकर आए। मैंने शिष्टाचार चाय के लिए पूछा तो बैठ गए। उनको सोफे पर बैठाकर मैं अंदर गया। श्रीमती जी से कहा कि नए वाले मकान में नए पड़ोसी आए हैं। जरा दो कप चाय बना दो।

पत्नी बोली- हां मुझे भी बुलवाया था। पर मैं भी ना जा सकी। कभी शाम-वाम को उन लोगों से मिलने चलेंगे। सुना है मकान का इंटीरियर बहुत अच्छा कराया है। पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे। पैसा अच्छा कमाया होगा। तब ही तो बड़ी कार है और बच्चे को विदेश में पढ़ बच्चे है।

श्रीमती जी के ज्ञान पर विस्तृत होते हुए मैंने कहा जब चाय बन जाए तो बता देना। मैं बाहर बैठता हूं। ड्राइंग रूम में आकर में सामने वाली कोच पर बैठ गया। जमुना प्रसाद जी बोले सुना है आप पत्रकार हैं और किसी स्वयं सेती संस्था से भी जुड़े हैं।

मैंने धीरे से कहा हा। जमुना प्रसाद जी खिल उठे। बोले अन्त: रिटायरमेंट के बाद में भी खाली समय मैं समाज सेवा करना चाहता हूं। आपसे मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आप क्या करना चाहते हैं, मैंने धीरे से कहा और चुपचाप सोचने लगा कि एक कमाऊ और भ्रष्ट सरकारी अफसर कैसी समाज सेवा कर सकता है।

जमुना प्रसाद जी ने समाज सेवा के बारे में अपने दर्शन से मुझे अवगत कराया। उनकी दृष्टि में समाज सेवा उनके आवास के आसपास की सड़कों पर सफाई, कॉलोनी के पार्क में घास और पौधों का रखाव और आसपास की सड़क पर झाड़ू लगाने की व्यवस्था थी। इसके साथ-साथ कॉलोनियों में कार पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त कराना भी बहुत जरूरी था। मैं उनके विचार सुनता रहा श्रोता कि उनके समाज सेवा के दर्शन शास्त्र मैं गरीब भूखे रहेंगे असहाय लोगों का कोई स्थान नहीं है। ना किसी कुमार और बेसहारा उड़द नारी पुरुष के बारे में कोई भी विचार दिया।

हां आप ठीक कह रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह सोचते हैं मैंने कहा। वह उत्साहित हुए। बोले देखिए समाज में हमें इतना कुछ दिया जय हमारा फर्ज है कि समाज के लिए कुछ करें वह बोले। बल्कि ठीक मैंने कहा और उठने का उपकरण करते हुए कहा जाने के लिए तैयार होने की बात कहते हुए क्षमा मांगी।

जमुना प्रसाद जी शायद और कुछ चाहते थे। चलिए फिर जब फुर्सत से हम लोग बैठ कर बात करेंगे। उन्होंने कहा और नमस्कार करके चले गए। लगभग एक महीने बाद जमुना जी या फिर प्रकट हुए। बड़े उत्साहित लग रहे थे। बोले मैंने सोचा कि समाज की सेवा करनी है तो चुनाव जनप्रतिनिधि बनना आवश्यक है। अगले महीने स्थानीय निकाय के चुनाव है। सोचता हूं चुनाव लड़ लो। क्या राय है आपकी। मैंने उनके चेहरे को देखा जिस पर लालच और महत्वाकांक्षा के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। फिर कहां आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। जमुना दास जी खिलाकर हंस पड़े. बोले- आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजनीति के क्षेत्र में तमाम छोटे-बड़े को जानते हैं। बिल्कुल मैंने कहा फिर उस दलित लड़की के बारे में सोचें लगा पिछले दिनों जिनको जिसको करके बड़ी जाति की कुछ लड़कों ने जिंदा जला दिया था।

जमुना प्रसाद जी बताते रहे कि हमारे वार्ड में कितने घर हैं और किस-किस के कितने कितने लोग हैं और चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ करना होगा। क्या चुनाव लड़ने में कुछ खर्चा भी आएगा मैंने मासूमियत से पूछा। हां 20-25 लाख तो लग ही जाएंगे। पर कोई बात नहीं अगर जीत गए तो उससे ज्यादा वापस आ जाएगा। वह यह कह कर बेशर्मी से मुस्कुराए।

मैं सोचता रहा कि कि नहीं हुए जनप्रतिनिधि बनकर अच्छी कमाई करना ही शायद समाज सेवा के लिए जरूरी होता है।

सुना कि जमुना प्रसाद जी चुनाव के मैदान में उतर गए हैं और प्रचार में पैसा ही पानी की तरह बहा रहे हैं। फिर एक दिन सुबह मेरे घर आए। मैं चाय की चुस्कियां लेकर अखबार पढ़ रहा था। मैंने कहा बैठो और श्रीमती जी को आवाज देकर कहा कि एक प्याला और लाओ जमुना प्रसाद जी आए हैं।

चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है मैंने पूछा। और तो सब ठीक है पर लोग कहते हैं कि मैं मेरे भाषण जरा कमजोर रहते हैं। इसी के बारे में आपकी मदद मांगने आया हूं, वह बोले मैंने कल रात में एक धुआंधार भाषण देने का प्रयास किया। उसे रिकॉर्ड करके आपके पास लाया हूं। कृपया इसको बताएं कि यह कैसा है। उन्होंने कहा और अपना मोबाइल फोन मेरी और बढ़ा दिया।

मैंने 10 मिनट तक उनके भाषण को सुना जो राष्ट्रवाद की भावना से ओत-प्रोत था। फिर सोचा कि इस पर क्या कमेंट करें।

कैसा लगा उन्होंने उत्सुकता से पूछा। और तो सब ठीक है पर आपने यह क्यों कहा कि बाबर की संतानों वापस जाओ मैंने पूछा।

देश विदेशों मुस्लिम आक्रांता मुगल सम्राट बाबर के साथ ही तो आए थे। अगर उनके वंशज हमारे धर्म और संस्कृति से करते हैं तो उन्हें मध्य एशिया वापस जाना चाहिए, जमुना प्रसाद जी बोले। मगर मुसलमान जो भावों से बहुत पहले भारत में आ गए थे। पहला मुस्लिम सुल्तान तो 52 से 300 साल पहले दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ऐसा लगा कि जुड़ा प्रसाद जी को कोई बहुत बड़ा झटका लगा हो। आवश्यक मिश्रित आकाश मैं बोले सचमुच। राजू की क्या बात है मैंने कहा। उन्हें मेरी बात पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। बोले मुसलमान भारत में बाबर से पहले आए हुए थे इस बात को कैसे कंफर्म किया जाए। मैंने मन ही मन माथा ठोक लिया। सोचा कि मूर्ख से साथ समय नष्ट हो रहा है। आप कंफर्म करना चाहते हैं तो इस स्कूल की किसी बच्चे की इतिहास की किताब देख लें। अत: वह अपने अज्ञान पर कुछ लज्जित लगे। बोले तो यह बात सबको पता है, और क्या मैंने कहा और उनका मोबाइल उनको वापस कर दिया।

(लेखक की आगामी व्यंग्य संग्रह : 'तोला माशा मीशा' से)

मीडिया मैप

उदार जनतंत्र का सजग प्रहरी

संरक्षक सदस्यता : रु. 50,000/-

आजीवन सदस्यता : रु. 20,000/- (व्यक्तिगत), रु. 40,000/- (संस्थागत)
विशेष सदस्यता : रु. 5000/- (व्यक्तिगत), रु. 10,000/- (संस्थागत)
सामान्य सदस्यता (5 वर्ष) : रु. 2500/- (व्यक्तिगत) और रु. 5000/- (संस्थागत)

(डॉक खर्च सहित)

1. हां मैं 'मीडिया मैप' हिन्दी मासिक पत्रिका का (व्यक्तिगत/संस्थागत) विशेष सदस्यता/आजीवन सदस्यता/संरक्षक सदस्यता के रूप में 'मीडिया मैप' के नाम नकद/चेक/डिमांड ड्राफ्ट नं : ..... दिनांक : ..... के रूप में धनराशि रु. ..... की सहयोग राशि संलग्न कर रहा/रही हूं।

2. मैंने दिनांक : ..... को नकद/चेक/डी.डी. ..... के माध्यम से 'मीडिया मैप' हिन्दी मासिक पत्रिका का (व्यक्तिगत/ संस्थागत) विशेष सदस्यता/आजीवन सदस्यता/संरक्षक सदस्यता के रूप में धनराशि रु. ..... कार्यालय के पता- 69 ज्ञानखंड-4 इंदिरापुरम, गाजियाबाद- 201014 (उत्तर प्रदेश) पर भेज दिया है।

3. मैंने 'मीडिया मैप' हिन्दी मासिक पत्रिका का (व्यक्तिगत/संस्थागत) विशेष सदस्यता/आजीवन सदस्यता/संरक्षक सदस्यता के रूप में धनराशि रु. ..... 'मीडिया मैप' के (भारतीय स्टेट बैंक, नीतिखंड इंदिरापुरम, गाजियाबाद के चालू खाता संख्या : **43812481024, IFSC** कोड नं.- **SBIN0005226)** में दिनांक..... को जमा करा दिए हैं। इसकी सूचना Email : editor@mediamap.co.in द्वारा भेज दी है।

मेरा पूरा विवरण निम्न प्रकार से है, कृपया मेरे पते पर 'मीडिया मैप' पत्रिका भेजने की कृपा करें।
पूरा नाम : ..... डाक का पता : .....
पिन कोड : ..... मोबाइल/फोन नं. : .....

हस्ताक्षर

मीडिया मैप **Media Map**

पंजीकृत कार्यालय : 2324, सेक्टर-डी,पॉकेट-2, वसंतकुंज, नई दिल्ली
Email : editor@mediamap.co.in, Contact: 9810385757/9910069262

नाम : ..... पता : ..... से नकद/चेक/डी.डी द्वारा
राशि. रुपया : ..... दिनांक : ..... को पत्रिका की सदस्यता हेतु प्राप्त किया।

(प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)

RNI NO. : UPHIN/2016/68336

See Media Map Website

Website link: www.mediamap.co.in

View Media Map YouTube

Media Map News

जनसंवाद 7 : खानपान पर रोक क्यों? Ep- 124

3 views • 4 hours ago

जन संवाद 6 : नेहा हो या कुणाल, व्यंग्य से क्यों डरना? Ep- 123

4 views • 4 hours ago

विविधा 15 : जज को भी छह महीनों की सजा : Ep- 122

27 views • 21 hours ago

विविधा- 14 : कंपनी की तानाशाही - आपके प्रोडक्ट को ख़राब कर रहें हैं। Ep- 121

6 views • 23 hours ago

आर्थिक सहयोग की अपील

उदार लोकतंत्र और गैर-सांप्रदायिक विश्वास के दर्शन से जुड़ा, मीडियामैप समाचार नेटवर्क एक गैर-व्यावसायिक संगठन है। हम आप जैसे गंभीर और समझदार पाठकों को संबोधित करना चाहते हैं। वरिष्ठ मीडियाकर्मियों के समूह द्वारा किया गया यह एक स्वैच्छिक प्रयास है, जिसका किसी राजनीतिक, सामाजिक या व्यावसायिक समूह से कोई संबंध नहीं है। मीडिया मैप के प्रकाशन को निरंतर व सुचारु रूप से जारी रखने हेतु आपका सहयोग आवश्यक है।

- ***State Bank of India***
- ***Account No. 43812481024***
- ***IFSC # SBIN0005226***
- ***प्रस्तुत QR कोड को स्कैन करें।***

प्रकाशक
MBKM Foundation, एक पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन

पंजीकृत कार्यालय
फ्लैट नंबर: 2332, सेक्टर-डी, पॉकेट-2, वसंत कुंज, दक्षिण दिल्ली

RNI No. : UPHIN/2016/68336

Please Stay with us and Explore the Beauty of the Surrounding Areas

Scholars Destination

PLEASE CONTACT

9045005700 | 9910322682 | www.sdmotel.com | info@sdmotel.com

BHALUGAAD WATERFALL

KAINCHI DHAM

MUKTESHWAR DHAM

CHAULI KI JALI